A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 03 जुलाई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 294, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

आखिर क्यों अटकी है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील ?

सौतिक बिस्वास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तय की गई 9 जुलाई की डेडलाइन पूरी होने के चंद दिन ही बचे हैं और दिल्ली-वॉशिंगटन के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद अब भी बनी हुई है, लेकिन बातचीत लगातार कठिन सौदेबाज़ी में उलझती जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट ने संकेत दिया था कि 'डील होनी तय' है और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्रंप के एक दावे के जवाब में घोषणा की थी कि दिल्ली एक 'बिग, गुड, ब्यूटीफुल' समझौते का स्वागत करेगी। ट्रंप ने दावा किया था कि दिल्ली के साथ एक ट्रेड डील होने जा रही है और यह भारतीय बाज़ार को 'खोलेगी।' बावजूद इन दावों के वार्ताकार मुश्किल बातचीत में उलझे हुए हैं।

मुख्य मुद्दे अब भी बने हुए हैं। ख़ासकर कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार खोलने, ऑटो पॉर्ट्स और भारतीय स्टील पर टैरिफ़ को लेकर। ट्रेड डील पर बात करने गए भारतीय वार्ताकारों ने एक और दौर की बातचीत के लिए रुकने की मियाद को बढ़ा दिया है। उधर, भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नहीं झुकने का संकेत दिया है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका भारतीय बाज़ार को और अधिक खोलने पर ज़ोर दे रहा है।

दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के एक पूर्व भारतीय व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं, 'अगले सात दिनों में तय हो जाएगा कि भारत और अमेरिका एक सीमित मिनी डील करते हैं या बातचीत की मेज से हट जाते हैं...कम से कम फ़िलहाल के लिए। कुछ मुद्दों पर अनिश्चितता बनी हुई है और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि। वॉशिंगटन के 'सेंटर फ़ॉर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़' पर नज़र रखने वाले रिचर्ड रोसोव ने बताया, 'एक शुरुआती समझौते तक पहुँचने में दो असली चुनौतियां हैं। पहले नंबर पर है- भारतीय बाज़ारों तक बुनियादी कृषि उत्पादों की अमेरिकी पहुँच। भारत को आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अपने बुनियादी कृषि क्षेत्र को बचाने की ज़रूरत होगी। सालों से वॉशिंगटन भारत के कृषि क्षेत्र में और बड़ी पहुंच के लिए दबाव डालता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां ग्रोथ की एक बड़ी संभावना है। लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा के साथ लाखों छोटे किसानों की आजीविका और हितों का हवाला देते हुए हुए पुरज़ोर तरीक़े से इसका विरोध किया है। दूसरा अहम मुद्दा है, 'ग़ैर टैरिफ़ अवरोध। भारत के बढ़ते 'क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स' (क्यूसीओ) जैसे मुद्दे अमेरिकी बाज़ार तक पहुँच में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं और व्यापार समझौते में इन्हें सार्थक ढंग से संभालना मुश्किल साबित हो सकता है।'

अमेरिकी ने भारत के बढ़ते और बोझिल आयात गुणवत्ता नियमों पर चिंता जताई है। 700 से अधिक क्यूसीओ आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य है निम्न गुणवत्ता वाले आयात पर अंकुश लगाना और घरेलू मैन्यूफ़ैक्चरिंग को बढ़ावा देना। वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि उत्पादों का निर्यात। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार आठ अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका मेवे, सेब और दालें भेजता है। लेकिन जैसे-जैसे व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है, वॉशिंगटन भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए मक्का, सोयाबीन और कपास के बड़े कृषि निर्यात के लिए दरवाज़े खोले जाने की मांग कर रहा है।

विशेषज्ञों को डर है कि टैरिफ़ में रियायतें भारत को अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और सार्वजनिक ख़रीद को कम करने के लिए दबाव डाल सकती हैं। ये दोनों भारतीय किसानों के प्रमुख कवच हैं जो उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम की गारंटी देकर उन्हें क़ीमतों में अचानक कमी से बचाते हैं और अनाज ख़रीद को सुनिश्चित करते हैं।

श्रीवास्तव कहते हैं, 'डेयरी उत्पादों या चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों पर टैरिफ़ में कोई कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन पर कृषि आधारित आजीविका दांव पर लगी हुई है। ये श्रेणियां राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 70 करोड़ से अधिक लोगों इससे प्रभावित होते हैं।'

'दिलचस्प बात है कि नीति आयोग के एक ताज़ा पेपर में प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चावल, डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सेब, बादाम और जीएम सोया सहित अमेरिकी कृषि आयात पर टैरिफ़ कटौती की सिफ़ारिश की गई है। हालांकि, यह साफ़ नहीं है कि यह प्रस्ताव आधिकारिक सरकारी नज़रिए को दिखाता है या महज एक नीतिगत सुझाव भर है। अगर अमेरिका कहता है कि भारत बुनियादी कृषि सेक्टर में पहुँच को शामिल नहीं करता है तो कोई डील नहीं होगी, तब ये साफ़ है कि अमेरिकी उम्मीदें सही तरीक़े से तय नहीं की गई थीं।'

श्रीवास्तव जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठ मई को अमेरिका-ब्रिटेन के बीच हुई मिनी ट्रेड डील के बाद, इसकी संभावना अधिक है कि 'वार्ता का नतीजा एक सीमित व्यापार समझौता हो।' प्रस्तावित डील के तहत, भारत कई औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ़ में कटौती कर सकता है, जिसमें ऑटोमोबिल सेक्टर शामिल है और जिसे लेकर अमेरिका की लंबे समय से मांग रही है। इसके अलावा भारत टैरिफ़ में कटौती करके और इथेनॉल, बादाम, अखरोट, सेब, किशमिश, एवोकाडो, जैतून का तेल, स्प्रिट और वाइन जैसे चुनिंदा उत्पादों पर कोटा तय करके कृषि क्षेत्र में सीमित पहुंच की मंज़ूरी दे दे।

'टैरिफ़ कटौती के अलावा, अमेरिका भारत पर तेल और एलएनजी से लेकर बोइंग विमान, हेलिकॉप्टर और परमाणु रिएक्टर तक बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल ख़रीद के लिए दबाव डाल सकता है। वॉशिंगटन मल्टी-ब्रैंड खुदरा क्षेत्र में एफ़डीआई को आसान बनाने की भी मांग कर सकता है, जिससे अमेज़ॉन और वॉलमार्ट जैसी फ़र्मों को फ़ायदा होगा और पुनः निर्मित वस्तुओं पर नियमों में ढील दी जा सकती है। अगर यह 'मिनी-डील' संपन्न हो जाती है तो यह टैरिफ़ कटौती और रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित होगी और सर्विस ट्रेड, बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार के साथ डिजिटल रेगुलेशन समेत एफ़टीए के तमाम व्यापक मुद्दों को भविष्य की बातचीत के लिए छोड़ दिया जाएगा।'

रोसोव कहते हैं, 'दोनों नेताओं यानी ट्रंप और मोदी, ने इस साल अपनी पहली मुलाक़ात में एक सरल सिद्धांत रखा था। लेकिन लगता है कि उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं।'

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वार्ता विफल हो जाती है तो इसकी कम संभावना है कि ट्रंप भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ़ दर को फिर से लागू करेंगे। इसके बजाय अधिकांश भारतीय आयातों पर मौजूदा एमएफ़एन दरों के ऊपर 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ़ लागू हो सकता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

फूल से ख़ुशबू चुराना – शाइरी तक ठीक है
चाँद-तारे तोड़ लाना- शाइरी तक ठीक है

धूप में कुछ दूर नंगे पाँव चल कर देखिए
आग पर चलना चलाना- शाइरी तक ठीक है

ये बहुत है उनके दुख में आप के आँसू बहें
दूध की नहरें बहाना- शाइरी तक ठीक है

आज कल सिंदूर तक तो ढंग का मिलता नहीं
माँग में तारे सजाना- शाइरी तक ठीक है

इक हवाई कैनवस पर शिद्दतों के रंग से
दर्द का चेहरा बनाना- शाइरी तक ठीक है

आप पहले शम्स से आँखें मिलाकर देखिए
शम्स को आँखें दिखाना- शाइरी तक ठीक है

आख़िरिश फिर दीप साहब आपका ज़ह्नी फ़ितूर
घूम-फिर कर आ गया ना शाइरी तक-ठीक है।

– भरत दीप माथुर

भोपाल समेत कई ज़िलों में बारिश, नदी-नाले उफने

- रतलाम का केदारेश्वर झरना फूटा , मऊगंज का बहुती जलप्रपात भी बहने लगा
- भोपाल में 3 इंच बारिश, बड़ा तालाब में पानी बढ़ा

निचले इलाकों में पानी भरा, हमीदिया रोड पर रेंगते हुए गुजर रही गाड़ियां

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, रतलाम, नीमच और राजगढ़ समेत कई जिलों में पानी गिरा। ये सिलसिला रुक-रुककर जारी है।

भोपाल में तो सुबह के समय इतना पानी गिरा कि सड़कों पर दो फीट तक पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रतलाम में कल्याण केदारेश्वर झरना बह निकला है। वहीं, मऊगंज के बहुती जलप्रपात में पानी बढ़ गया है। अगले 24 घंटे में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर चलेगा।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने राजगढ़, आगर-मालवा, अशोकनगर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सतना, श्योपुर, भिंड और गुना में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मैहर, सिंगरौली, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

हमीदिया रोड पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती रहीं

भोपाल में मंगलवार-बुधवार की रात में करीब 3 इंच बारिश हो गई। इससे बड़ा तालाब में पानी का लेवल आधा फीट तक बढ़ गया है। बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। अल्पना टॉकीज तिराहे की सड़क पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती हुई चल रही है। बारिश की वजह से भोपाल के सीवेज सिस्टम की पोल भी खुल गई है। हमीदिया रोड पर पिछले एक साल से सड़क और नाले का निर्माण चल रहा है। बावजूद पहली ही तेज बारिश में सड़क पर एक फीट तक पानी भर गया है। इस कारण बुधवार सुबह से ही वाहन रेंगते हुए गुजर रहे हैं। कई लोग रेलवे स्टेशन भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकारी प्रेस के पास अंबेडकर ब्रिज की सर्विस रोड पर भी पानी की निकासी नहीं होने से जलभराव की स्थिति बन गई है।

सरकारी प्रेस के पास अंबेडकर ब्रिज में पानी भरा

सरकारी प्रेस के पास अंबेडकर ब्रिज की शुरुआत में ही पानी भर गया। इससे राहगीरों को गुजरने में दिक्कतें हो रही हैं।

नादरा बस स्टैंड पर पानी भराया- नादरा बस स्टैंड के पास भी सड़क पर पानी भरने से दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। टू व्हीलर और पैदल राहगीरों को गुजरने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही हैं। यहां सड़क पर एक फीट तक पानी भरा हुआ है।

केंद्र सरकार से मिली पीएम मित्र पार्क की सौगात

- प्रदेश के विकास और कपड़ा उद्योग में नए युग का शुभारंभ : सीएम
- पीएम मित्र पार्क के प्रथम चरण में विकास कार्यों की प्रक्रिया प्रारम्भ

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का माना आभार

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री मित्र पार्क के प्रथम चरण में अधोसंरचना विकास की प्रक्रिया आरंभ होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह का हृदय से आभार माना है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा धार की 2158 एकड़ भूमि पर लगभग 2050 करोड़ की लागत से विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क के लिए हाल ही में 773 करोड़ रुपए लागत के टेंडर जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह पहल मध्यप्रदेश में कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल सेक्टर) को नई गति प्रदान करेगी। मध्यप्रदेश लगातार विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दी गई पीएम मित्र पार्क की सौगात निश्चित रूप से प्रदेश के विकास और कपड़ा उद्योग में नए युग का शुभारंभ करेगी।

फर्स्ट फेज के लिए हुए टेंडर

धार जिले के पीएम मित्र पार्क के पहले चरण के निर्माण कार्यों के लिए 773 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है और कहा है कि यह सौगात कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में एमपी के लिए नई शुरुआत साबित होगी। बुधवार को एक्स पर किए गए ट्वीट में सीएम डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश को एक और सौगात दी है। धार जिले में 2158 एकड़ भूमि पर लगभग 2050 करोड़ से अधिक की लागत से पीएम मित्र पार्क विकसित होने वाला है। पीएम मित्र पार्क के फर्स्ट फेज के अधोसंरचना विकास के लिए 773 करोड़ रुपए की लागत के टेंडर 30 जून 2025 को जारी कर दिए गए हैं। धार इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनेगा।

कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में जब मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है तो यह सौगात प्रदेश के विकास और कपड़ा उद्योग में नए युग की शुरुआत होगी। सीएम यादव ने कहा कि वे मध्यप्रदेश वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं।

कोविड के बाद अचानक मौतों पर स्टडी

बड़ा दावा-वैक्सीन से इसका संबंध नहीं

- 18 से 45 साल के लोगों पर हुई रिसर्च

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौत पर आधारित है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। स्टडी ने पुष्टि की है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइडइफेक्ट के मामले रेयर हैं। स्टडी में बताया गया है कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजहें हो सकती हैं। इनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। आईसीएमआर और एनसीडीसी अचानक होने वाली मौतों की वजह समझने के

लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए दो रिसर्च स्टडी की जा रही हैं। पहली पिछले डेटा पर आधारित थी और दूसरी रियल टाइम इन्वेस्टीगेशन से जुड़ी है। पहली स्टडी-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने मई, 2023 से अगस्त, 2023 तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों पर स्टडी की।

ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा

- टिहरी में कांवड़ियों से भरा ट्रक पलटा, 3 की मौत, 16 घायल

टिहरी (एजेंसी)। उत्तराखंड के टिहरी जिले में ऋषिकेश-गंगोत्री हाइवे पर बुधवार सुबह बड़े हादसे की सूचना है। जाजल और फकोट के बीच कांवड़ यात्रियों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में तीन

कांवड़ियों की मौत हो गई। वहीं, ट्रक में सवार 16 तीर्थयात्रियों के घायल होने की सूचना है। हादसे के समय ट्रक में कुल 19 कांवड़ यात्री सवार थे। वे ऋषिकेश से गंगोत्री की ओर यात्रा कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन हो सकते हैं सस्ते

- मोदी सरकार की जीएसटी स्लैब कम करने की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में इनकम टैक्स में कई रियायतें देने के बाद केंद्र सरकार अब मिडिल-क्लास और लोअर-इनकम फैमिली को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 12 फीसदी जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने या वर्तमान में 12 फीसदी टैक्स वाले आइटम्स को 5 फीसदी स्लैब में ला सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस रिस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव में मिडिल-क्लास के यूज में आने वाले आइटम्स शामिल होंगे।

अब आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग का हो गया आगाज

- गृहमंत्री अमित शाह बोले- अब मिलेगा बहुत जल्द इंसाफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों नए कानूनों के लागू होने के एक साल पूरा होने को नए युग का आगाज करार दिया है। इस अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगले तीन साल के भीतर नई आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से काम करने लगेगी और तब किसी भी नागरिक को तीन साल के भीतर न्याय मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। आम जनता के लिए नए कानूनों

की अहमियत बताते हुए अमित शाह ने कहा कि इससे आम लोगों में एफआईआर करेंगे तो क्या होगा की जगह एफआईआर से तुरंत न्याय मिलेगा का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में न्याय से युक्त शासन का स्वर्णिम कालखंड शुरू होगा।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 03 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

कर्नाटक के हासन में 'दिल' दे रहा है 'दगा'

● एक महीने के अंदर हार्ट अटैक से 20 की मौत ● लोगों में भय का है माहौल,मरने वाले सभी युवा ● सीएम सिद्धा रमैया ने कोविड वैक्सीन को कोसा

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के हासन जिले में डरा देने वाली खबर आई है। पिछले 24 घंटों में यहां छह लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि मौत का सही कारण जानने के लिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं डाटा देखा गया तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। यहां एक महीने के बाद 20 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। मरने वाले बुजुर्ग नहीं, बल्कि युवा है। इसी बीच सीएम सिद्धारमैया ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया है कि पिछले एक महीने में हासन जिले में दिल के दौरे से 20 लोगों की मौत हुई है। संजय, हासन जिले के सोमेनहल्लीकोप्पालु के रहने वाले 27 वर्षीय युवक थे। वह सोमवार शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करते समय गिर गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी शादी को 2 साल हुए थे। हर्षिता, हासन की रहने वाली 22 वर्षीय युवती थीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में उनकी मौत हो गई।

वह शिवमोग्गा में अपने माता-पिता के घर आई हुई थीं। उनकी शादी हो चुकी थी और वह हासन में रहती थीं। लेपाक्षी, 50 वर्षीय गृहिणी थीं। सोमवार को सुबह 7.45 बजे हासन स्थित अपने घर पर उन्हें पीठ में दर्द हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का अचानक काम करना बंद कर देना। मुत्तैया, 58 वर्षीय अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। हासन जिले के चन्नरायपटना शहर में अपने कॉलेज के सामने चाय पीते समय वे गिर गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कुमार, 53 वर्षीय किसान थे।

उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लोहित, सेना के एक अधिकारी थे और छुट्टी पर थे। हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई। वे 20 साल से सेना में थे। लोहित की शादी को सात साल हो चुके थे। उन्हें 3 जुलाई को ड्यूटी पर वापस जाना था लेकिन मौत हो गई।

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तकरार

● चुनाव आयोग के पास जा रहा विपक्ष, लगाए गंभीर आरोप

पटना (एजेंसी)। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों की एक संयुक्त टीम बुधवार को निर्वाचन सदन में चुनाव आयोग से मुलाकात करने की तैयारी में है। हालांकि इस बैठक को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि सभी दलों की ओर से चुनाव आयोग को पुष्टि नहीं मिली है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, 30 जून को कांग्रेस के एक कानूनी सलाहकार द्वारा आयोग को ईमेल भेजा गया था। इसमें 2 जुलाई यानी आज के लिए बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आपातकालीन मुलाकात का समय मांगा गया था। लेकिन, सभी दलों की तरफ से अब तक पुष्टि न मिलने के कारण यह बैठक स्थगित भी हो गई है। सूत्रों के अनुसार ई-मेल में दावा किया कि वे एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा उन्होंने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में शामिल लगभग सभी दलों के नाम लिए। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने इन दलों से बैठक के लिए पुष्टि करने को कहा था, लेकिन अब तक उसे दलों से पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए बैठक को स्थगित करना पड़ा है। इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि उन्होंने बुधवार को आयोग के समक्ष अपनी पार्टी का पक्ष रखने की पूरी तैयारी कर ली है और उन्हें बैठक रद्द होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों को समय न देने का आरोप लगाया। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने इस कदम को लोकतंत्र विरोधी और संविधान के खिलाफ करार दिया है।

उनका दावा है कि यह प्रक्रिया गरीब, ग्रामीण, और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है। भाकपा (माले) के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने बातचीत में कहा, मैं चुनाव आयोग के साथ होने वाली संयुक्त विपक्षी बैठक में उपस्थित रहूंगा। हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को अगुवाई देने का फैसला विपक्षी दलों ने पहले ही कर लिया था। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता पंजीकरण से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा,जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, आप उसी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

विस अध्यक्ष तोमर ने दी खंडेलवाल को बधाई

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन इकाई के निर्वाचन में श्री हेमंत खंडेलवाल के निर्विरोध निर्वाचन पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की है। श्री तोमर ने कहा है कि श्री हेमंत खंडेलवाल का सुदीर्घकालीन संगठनात्मक अनुभव, संगठन के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, सहजता, सादगी एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीय लगाव उनके इस पद पर चयन को प्रतिपादित करता है। उन्होंने कहा कि श्री खंडेलवाल बैतूल संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं बैतूल विधानसभा से दो बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। श्री खंडेलवाल बैतूल जिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं कुशाभाउ ठाकरे भवन निर्माण समिति के प्रमुख एवं प्रदेश संगठन में कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। उनका संगठनात्मक अनुभव कार्यकर्ताओं को नई दिशा प्रदान करने में सहायक होगा। श्री तोमर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश संगठन नई ऊर्जा, नवाचार और समन्वय के साथ और अधिक सशक्त होगा तथा कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखकर राष्ट्र प्रथम के हमारे ध्येय की ओर अग्रसर होगा।

मुश्किल में बादशाहत, डोलने लगा है डॉलर का सिंहासन

● अमेरिकी करेंसी के साथ 52 साल में पहली बार हुआ खेला

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका की करेंसी डॉलर कई दशक से दुनिया पर राज कर रही है लेकिन हाल के वर्षों में इसका दबदबा कम हुआ है। इस साल तो डॉलर की हालत लगातार पतली होती जा रही है। साल के पहले 6 महीनों में डॉलर इंडेक्स में 10.8 फीसदी गिरावट आई है। यह साल 1973 में गोल्ड ब्रेटन वूड्स सिस्टम खत्म होने के बाद डॉलर का सबसे खराब प्रदर्शन है। इस सिस्टम को 1944 में बनाया गया था। इसमें डॉलर और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के लिए गोल्ड को आधार बनाया गया था। डॉलर के लिए 2009 के बाद किसी 6 महीने में यह सबसे खराब प्रदर्शन है। साथ ही ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स में लगातार छठी महीने गिरावट आई है। इससे पहले आठ साल पहले यह इंडेक्स इतने लंबे समय तक गिरा था। अमेरिकी डॉलर में इस साल स्विस फ्रेंक को मुकाबले 14.4 फीसदी,यूरो के मुकाबले 13.4 परसेंट गिरावट आई है।

70 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले कजाकिस्तान में हिजाब बैन

● राष्ट्रपति बोले-राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहनें

अस्ताना (एजेंसी)। कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े, जिनसे किसी की पहचान छिपती है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहने जा सकते। राष्ट्रपति तोकायेव ने कहा- चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों की बजाय हमारे राष्ट्रीय कपड़े पहनना बेहतर है। ये कपड़े हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि, बीमारी, खराब मौसम, खेल, या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसकी छूट है।

ओला-उबर से सफर होगा 'डबल' महंगा

● केन्द्र ने पीक ऑवर्स में फेयर बढ़ाने की दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आप ऑफिस आने जाने के टाइम या शाम के पीक ऑवर्स में ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं, तो अब जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत एप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अब पीक ऑवर्स में बेस फेयर का दोगुना तक किराया वसूल सकेंगी। केंद्र

सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की हैं। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना (2×2) तक किराया वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा 1.5 गुना थी। क्लास के लिए राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइड किराया लगेगा।

पीएम मोदी घाना, ब्राजील समेत 5 देशों के दौरे पर रवाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। यह आठ दिवसीय दौरा, 2 से 9 जुलाई तक चलेगा, पिछले दस सालों में उनकी सबसे लंबी राजनयिक यात्रा होगी। इस दौरान वह घाना, त्रिनिदाद-टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। ब्राजील में वह 6-7 जुलाई को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत घाना से होगी। यहां पीएम 2 से 3 जुलाई तक रुकेंगे। यह तीन दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस दौरान वह घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और आर्थिक, ऊर्जा, और रक्षा सहयोग को नई

● ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल, आर्थिक और रक्षा संबंधों पर जोर

मंजिलें देने पर बात होगी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और गहरा करने का यह सुनहरा

मौका होगा। इसके बाद, पीएम मोदी 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद-टोबैगो पहुंचेंगे। यह 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। इस यात्रा से भारत और इस कैरेबियाई देश के बीच व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ताकत मिलेगी। दौरे का तीसरा पड़ाव अर्जेंटीना में होगा। पीएम मोदी 4-5 जुलाई को रहेंगे। वहां वह रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर देंगे। यह दौरा भारत और अर्जेंटीना के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को नया आयाम देगा। इसके बाद पीएम 5-8 जुलाई तक ब्राजील का दौरा करेंगे। समिट के बाद राष्ट्रपति सिल्वा पीएम मोदी के लिए स्पेशल डिनर की मेजबानी करेंगे। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी वैश्विक प्रशासन के सुधारों, शांति एवं सुरक्षा, बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने, जिम्मेदारी के साथ एआइ के इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए जरूरी कदमों और वैश्विक स्वास्थ्य पर बात करेंगे।

क्वाड में पाकिस्तानी मंसूबों को लग गया तगड़ा झटका

● पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता

आसिम मुनीर को सख्त चेतावनी,चीन की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर भारत को अप्रत्याशित सफलता हाथ लगी है। इस बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान-प्रायोजित इस आतंकवादी हमले में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक की आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। क्वाड के विदेश मंत्रियों की ओर से इस मसले पर भारत की भावना का समर्थन करते हुए एक सुर में निंदा करना व आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता शामिल रही।

बैचमेट लड़की बोली-आरोपी लौटा तो एडमीशन घटे थे

● कॉलेज में लड़कियों की तस्वीरें लेता, डर से लड़कियां क्लास छोड़ देती थीं

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट से गैंगरेप के आरोपी मनोजीत की बैचमेट रही एक लड़की ने कॉलेज में उसके आतंक के बारे में बताया है। इसके मुताबिक कॉलेज में लौटने के बाद मोनोजीत ने सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। मनोजीत से बचने के लिए ही उसने भी कॉलेज जाना छोड़ दिया था। मनोजीत मिश्रा को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 2024 में वह एडहॉक पर कॉलेज स्टाफ में आया तो उस कॉलेज में एडमीशन रेट घट गया था।

इतना ही नहीं, कुछ लड़कियों ने बताया कि मनोजीत की मौजूदगी में उन्हें डर बना रहता था। वह कैंपस में लड़कियों तस्वीरें लेता, ग्रुप में पोस्ट करता था। हर दूसरी लड़की को प्रपोज करता था। आरोपी को छात्रों और प्रशासन के बीच देवता का दर्जा प्राप्त था। कैंपस के हर दस्तावेज तक उसकी पहुंच थी। हर स्टूडेंट की डीटेल, फोन नंबर और पते उसके पास होते थे। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को गैंगरेप एक छात्रा से गैंगरेप हुआ था। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा यहीं का पूर्व छात्र है। बाकी 2 आरोपी मौजूदा स्टूडेंट्स हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। मामले में तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन बौद्ध परंपराओं से होगा

● इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं,चीनी प्रवक्ता बोले-केंद्र सरकार की परमीशन लेनी होगी

धर्मशाला (एजेंसी)। हिमाचल के धर्मशाला में बुधवार को शुरू हुए 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के मौके पर दलाई लामा की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि दलाई लामा की संस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। साथ

ही उन्होंने यह भी क्लियर किया कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा। तिब्बत और बौद्ध धर्म में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर चीन ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा- दलाई लामा के पुनर्जन्म को चीनी कानूनों और नियमों के साथ-साथ धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का भी पालन करना होगा। बता दें कि धर्मशाला स्थित दलाई लामा लाइब्रेरी एंड आर्काइव में 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के प्रमुख लामाओं, तिब्बती संसद, सिविल सोसाइटी, संगठनों और दुनिया भर से आए तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि भाग

ले रहे हैं। 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गादेन फोडंग ट्रस्ट को सौंपी है। उन्होंने दोहराया कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकार केवल ट्रस्ट को है। कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दलाई लामा ने कहा कि ट्रस्ट के अलावा कोई और अगले दलाई लामा की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस घोषणा ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि चीन मौजूदा दलाई लामा की मौत के बाद खुद 15वें दलाई लामा की नियुक्ति कर देगा। दलाई लामा ने अपने वीडियो संदेश में कहा- 1969 में ही हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि संस्था को जारी रखने का निर्णय संबंधित लोगों को करना चाहिए।

भोपाल होगा भिक्षावृत्ति मुक्त

- आश्रम स्थल संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं से 15 जुलाई तक प्रस्ताव आमंत्रित

भोपाल (नप्र)। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल उपयोजना के तहत भोपाल जिला को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से चयनित किया गया है। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विशेष रूप से आश्रय स्थल/भिक्षुक गृह की स्थापना की जाना है। इस आश्रय स्थल के संचालन के लिए अनुभवी और सक्षम स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों से 15 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर भोपाल द्वारा 3 फरवरी 2025 को भिक्षावृत्ति करने व भिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि जो संस्थायें निम्न शर्तें पूर्ण करती है वह आवेदन कर सकती है इसके लिये-

- संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन/फर्म/लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो।
- वर्तमान वैध कार्यकारिणी हो।
- कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हो।
- संस्था किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड न हो।
- विगत 5 वर्षों से पुनर्वास संबंधित कार्य का अनुभव हो।
- वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो (पिछले 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक)।
- संस्था के उपविधियों में भिक्षावृत्ति पुनर्वास संबंधी उद्देश्य शामिल होना आवश्यक है।
- इच्छुक संस्थाएँ अपना प्रस्ताव संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, शेड नं. 01, कमिश्नर कार्यालय के पीछे, पुराना सचिवालय, भोपाल में डाक, स्वयं उपस्थित होकर, या ईमेल के माध्यम से भेज सकती है।

भोपाल में खाद्य विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला

- अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर फोकस, आईटीसी और जोमैटो के विशेषज्ञ भी शामिल

भोपाल (नप्र)। भोपाल स्थित पलाश रेसीडेंसी में बुधवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला हो रही है। इसमें प्रदेशभर से खाद्य विभाग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन और मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। साथ ही नवीनतम नियमों, नीतियों, नवाचारों और विभागीय कार्यप्रणालियों जैसे मिलिंग, भंडारण, उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-ऑफिस, ई-सीआर, आई गॉट आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

विशेषज्ञ भी हुए शामिल

कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं पर सुना जाएगा। साथ ही उनके सुझावों पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा आईटीसी, जोमैटो और अन्य निजी एजेंसियों के विशेषज्ञों अधिकारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष फोकस करेंगे।

ऑनलाइन बिल प्रक्रिया पर भी चर्चा

इस दौरान उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक सत्यापन, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया की समीक्षा तथा अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है। यह कार्यशाला विभाग की कार्यशैली को अधिक पारदर्शी, तकनीकी और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यशाला का मार्गदर्शन अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त कर्मवीर शर्मा और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा द्वारा किया जा रहा है।

सीआर पर अभिमत न दिया तो होगी कार्रवाई

- जीएडी ने कहा, टाल-मटोल की तो खुद की सीआर खराब कराएंगे रिपोर्टिंग अफसर

भोपाल (नप्र)। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की सीआर बुलाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों जारी किए हैं। इसके बाद विभाग ने 20 अप्रेल 2023 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर तय समय अवधि में किसी अधिकारी ने कर्मचारी के सीआर पर अपना अभिमत रिपोर्टिंग अधिकारी या रिव्यू करने वाले अधिकारी या फिर स्वीकार कर्ता अधिकारी ने अपना अभिमत नहीं दिया तो उस पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ उसके सीआर में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। जीएडी के उपसचिव द्वारा एक जुलाई को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी से प्राप्त सेल्फ असेसमेंट और उसके बाद की स्थिति में सीआर में अपना अभिमत नहीं लिखा तो उसे गंभीरता से लेकर कार्यवाही की जाएगी।

पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन : मंत्री सारंग

पैक्स का सुदृढ़ीकरण जरूरी

अधीनस्थ पैक्स तक संभागीय और जिला अधिकारी करें दौरा, समन्वय भवन में राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला

भोपाल (नप्र)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए पूरी सहकारिता की टीम कृत-संकल्पित होकर काम करें। मंत्री श्री सारंग बुधवार को समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

श्री सारंग ने कहा कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए संभागीय और जिला अधिकारी अधीनस्थ पैक्स का निरीक्षण करें। मुख्यालय के अधिकारियों को भी संभागवार जिम्मेदारी दी जाए, जो उनके अधीनस्थों की समस्या एवं सुझावों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सहकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केडिट मूवमेंट के साथ सहकारिता के विभिन्न आयामों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता का क्लेवर बदल रहा है। सहकारी आंदोलन को पुनः मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। श्री सारंग ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से ही गरीबों के घर में खुशी लायी जा सकती हैं। सहकारिता ही ऐसा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हर घर में रोजगार के नए अवसर पैदा किये जा सकते हैं। सहकारिता की साख के लिए काम करें। लोगों को अच्छे कामों के लिए याद रखा जाता है। ईमानदारी से किया गया कार्य आत्मसंतुष्टि देता है, इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन जरूरी है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन मध्यप्रदेश का रहा। इसके लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की नवाचार विंग और सीपीपीपी मॉडल को भूरी-भूरी प्रशंसा मिली है। यही नहीं कंप्यूटराइजेशन की दिशा में भी मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर रहा है, जो सराहनीय है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कमिटमेंट दक्षता को सिद्ध करता है। सभी टीमवर्क के साथ काम करें। यूनिफार्मलिटी जरूरी है। साफ सुथरा ईमानदारी से किया गया कार्य ही आपकी पहचान बनेगा जिससे आपका नाम होगा। जॉब के लिए ईमानदार रहेंगे, तो सफल होंगे। मंत्री श्री सारंग ने शुरूआत में संभाग और जिलों के आए अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और बिना बताए अनुपस्थित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

पैक्स सुदृढ़ हो, यही लक्ष्यः एसीएस वर्णबालः अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णबाल ने कहा कि हर पैक्स को केडिट के अलावा तीन एक्टीविटी करना जरूरी है। स्थानीय पृष्ठभूमि में अवसरों को तलाश कर बिजनेस बढ़ाना होगा। संभागीय और जिला अधिकारी को एक-एक पैक्स की समयबद्ध तरीके से समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि पैक्स सुदृढ़ हो यह लक्ष्य होना चाहिये। बिजनेस सोसायटियों के सदस्यों के खाते हमारे यहां होना चाहिये। साथ ही उनके लिये माइक्रो एटीएम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प ने कहा कि सहाकारिता के सकारात्मक बदलाव के दौर में अधिकारी अपनी अहम भूमिका को पहचानकर दायित्वों का निर्वहन करें। सहकारिता के मॉडलाइजेशन को धरातल पर क्रियान्वित करें। अधिकारी अपनी लीडरशिप में प्रगति का फॉलोअप लें और पैक्स को बिजनेस यूनिट बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता ने स्वागत भाषण में कार्यशाला में हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उप सचिव श्री मनोज सिन्हा ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत करवाया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त, जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समिति प्रबंधकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ब्रिज पर कार पलटी वहीं पर वैन टकराई

वैन में स्कूली बच्चे सवार थे, 6 घंटे में एक ही जगह पर दो हादसे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के प्रभात नगर से एमपी नगर की ओर जाने वाले ब्रिज पर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार एसयूवी कार बेकाबू होकर पलट गई। इसी जगह बुधवार करीब सुबह 8 बजे एक स्कूली वैन डिवाइडर से टकरा गई।

वैन में स्कूली बच्चे सवार थे। दोनों ही मामलों में थाना प्रभारियों ने जानकारी होने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक क्रेटा कार ब्रिज पर तेज रफ्तार में दौड़ती दिखाई दे रही है। पीछे चल रहे राहगीर इसका वीडियो बना रहे थे। तभी कार कुछ दूरी पर जाने के बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार का एक पहिया टूटकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों ने कार में फंसे तीन लोगों को बाहर निकाला। तीनों होश में थे, जिसके बाद उन्हें जेपी अस्पताल पहुंचाया गया। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। कार में टैक्सी नंबर प्लेट लगी थी।

इसी स्पॉट पर सुबह दूसरा हादसा हुआ: एक स्कूल वैन बुधवार सुबह ठीक इसी स्थान पर डिवाइडर से टकरा गई। तेज बारिश के चलते वैन के फ्रंट ग्लास में फॉग जम चुकी थी, जिससे चालक को रोड नहीं दिख पाई। हालांकि रफ्तार ज्यादा न होने के कारण वैन डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गई थी। बाद में स्कूली बच्चों को वैन से निकाला गया और दूसरे वाहन से स्कूल तक पहुंचाया गया।

टीआई बोले- हादसे की जानकारी नहीं: दोनों घटनाओं के संबंध में एमपी नगर थाने के टीआई जयहिंद शर्मा ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं है। इधर, ऐशबाग थाने के टीआई वीबीएस सेंगर ने बताया कि ब्रिज के जिस हिस्से में घटना हुई वह एमपी नगर थाना क्षेत्र में आता है।

नागौद सब-स्टेशन में अब डबल एक्स्ट्रा हाईटेंशन सप्लाई की सुविधा

सतना और देवेंद्रनगर दोनों से रहेगी विद्युत आपूर्ति

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में विद्युत पारेषण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विश्वसनीयता के लिए सतना जिले में स्थित 132 के.व्ही. सब स्टेशन नागौद को अब डबल एक्स्ट्रा हाईटेंशन सप्लाई से जोड़ा गया है। यह सब-स्टेशन अब वैकल्पिक व्यवस्था के साथ दोहरी आपूर्ति प्रणाली पर कार्य करेगा। श्री तोमर ने बताया कि पूर्व में यह सबस्टेशन एक रेडियल सब-स्टेशन के रूप में क्रियाशील था, जहां से 132 के.व्ही. की विद्युत आपूर्ति केवल 220 के.व्ही. सिल्पारा (सतना) सब-स्टेशन से प्राप्त होती थी।

441 लाख रुपए से हुआ विस्तार: क्षेत्र में अधिक विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण एवं सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा 441 लाख रुपये की अनुमानित लागत से देवेन्द्र नगर से एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइन अब नागौद तक विस्तारित की गई है। परिणामस्वरूप अब किसी एक सर्किट में शटडाउन या ब्रेकडाउन की स्थिति में भी उपभोक्ताओं को विद्युत बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री राजेश द्विवेदी के अनुसार यह व्यवस्था, 132 के.व्ही. नागौद-देवेंद्रनगर (पन्ना) 27.6 किलो मीटर और 132 के व्ही नागौद -सतना 18.9 किलोमीटर लाइन के सर्किट को 'लाइन इन-लाइन आउट' (लिलो) कर नागौद से जोड़े जाने से संभव हो सकी है। इस नई व्यवस्था से देवेंद्रनगर, वसुधा, रहिकवाड़ा, नागौद, सिंहपुर, जसो, कटन और सलेहा क्षेत्र के 42,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान के साथ उच्च शिक्षा मंत्री परमार की चर्चा

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के परिप्रेक्ष्य में कार्यों, नवाचारों और प्रगति से अवगत कराया

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल में भेंट कर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को लेकर सारगर्भित चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के नीतिगत निर्णयों, शिक्षा में किए जा रहे कार्यों एवं नवाचारों से अवगत कराया।

श्री परमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में प्रदेश के समस्त जिलों में स्थापित किए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और उनमें भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ की स्थापना एवं प्रगति के सम्बंध में अवगत कराया। श्री परमार ने पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परम्परा के दृरुतगति से समावेश के लिए विभिन्न कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों से प्राप्त अनुशंसाओं की जानकारी भी दी। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषा के समावेश के लिए हो रहे कार्यों की जानकारी से भी अवगत कराया। श्री परमार ने विद्यार्थियों के गुणात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने, उद्योगजगत की आवश्यकता अनुरूप रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की समावेशिता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए किए जा रहे कार्यों एवं प्रगति से भी अवगत कराया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ संजय गोयल, आयुक्त तकनीकी शिक्षा श्री अवधेश शर्मा सहित उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नगदी रहित उपचार स्कीम

डिवीजनल कमिश्नर को योजना की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश

भोपाल (नप्र)। देश में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। समय-समय पर यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी गाइड-लाइन्स की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये नगदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किये हैं। निर्देशों में बताया गया है कि यह स्कीम और गाइड-लाइन्स मई-2025 और जून-2025 में जारी हुई हैं। इसी के साथ मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2025 को यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया है। निर्देशों में बताया गया है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहाँ दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाये गये फण्ड से स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिये जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फण्ड से किया जायेगा। योजना में अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के लिये एक लाख 50 हजार रूपये तक के उपचार की व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नम्बर 112 में खबर दे सकता है।

सांप से खेल रहा था शख्स, पकड़ ढीली हुई, हमला किया

हथेली और कंधे पर काटा, शरीर में फैला जहर ; वेंटिलेटर सपोर्ट पर है पीड़ित

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पिपलिया पेंदे खान निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति पर कोबरा के साथ खेलना भारी पड़ गया। घर के बाहर सांप देखते ही व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वह उसे लेकर पूरे इलाके में घूमने लगा, जिसका मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। करीब 10 मिनट तक व्यक्ति लगातार सांप को परेशान करता रहा। कभी उसको पालतू जानवर की तरह सहलाना तो कभी आसपास के लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करना। इसी बीच उसकी पकड़ ढीली हुई और सांप ने पहले उसकी हथेली और फिर कंधे पर काट लिया।

वेंटिलेटर पर भर्ती पीड़ितः एम्स भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार, कोबरा को लंबे समय तक परेशान किया गया, जिससे सांप तनाव में आ गया था। यही वजह रही कि उसने मौका मिलते ही बड़ी मात्रा में जहर व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इसके कारण सिर्फ 30 मिनट में ही व्यक्ति में न्यूरोलॉजिकल लक्षण सामने आने लगे। जहर की मात्रा ज्यादा होने के कारण मरीज को अगले 30 मिनट में लगातार जरूरी इलाज दिया गया, इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। स्थिति को बिगड़ता देख उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मरीज की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

सांप भाग निकलाः पीड़ित को जैसे ही कोबरा ने काटा, वह घबरा गया। आसपास मौजूद लोग भी डर के चलते दूर हो गए। इसी बीच सांप मौका देखते ही भाग निकला। आसपास के लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में अक्सर क्षेत्र में सांप निकलते हैं। ज्यादातर रैट स्नेक (गैर-जहरीला) दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार कोबरा भी निकलता है। इस घटना से लोगों में डर बैठ गया है।

घटना का वीडियो आया सामनेः सांप को पकड़ कर घूमते हुए व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो की शुरुआत में ही एक महिला कोबरा को एम्स की तरफ छोड़ने की बात कहती सुनाई दे रही है। करीब 38 सेकेंड के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि व्यक्ति सांप के साथ एक पालतू जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था। एम्स के डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि यदि सांप नजर आए तो उससे दूरी बनाए रखें।सांप इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करते हैं। यदि घर में सांप हो तो स्नेक कैचर को ही फोन करें, खुद उसे पकड़ने का प्रयास न करें। डॉक्टरों ने यह भी अपील की कि इन दिनों कई नकली सपेरे भी घूम रहे हैं, सांप उन्हें न ले जाने दें। वे सांप के मुंह को फैवी क्विक से चिपका देते हैं, जिससे सांप कुछ दिनों में तड़प-तड़प कर मर जाता है।

संपादकीय

मप्र भाजपा- युवा हाथों में कमान

भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्विरोध मप्र भाजपाध्यक्ष चुने जाने से जहां पार्टी की राज्य इकाई को नया नेतृत्व मिल गया है, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सत्ता के साथ-साथ संगठन पर भी पकड़ मजबूत हो गई है, क्योंकि हेमंत सीएम की पहली पसंद माने जा रहे थे। साथ ही उन्हें संघ नेता सुरेश सोनी का समर्थन भी मिला। भोपाल में पार्टी की एक जुलाई की बैठक में जो हुआ, वह तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक ही था। इस पद के लिए हवा में चाहे जितने नाम तैर रहे हों, दावेदारियां की जा रही हों, लेकिन अंदरखाने तय हो गया था कि हेमंत खंडेलवाल को ही अध्यक्ष बनाना है। आलाकमान ने भी हेमंत को अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दे दिया कि राज्य में मुख्यमंत्री की पसंद को उसकी भी हरी झंडी है। खुद सीएम ने हेमंत के नाम का प्रस्ताव किया। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में और किसी ने नामांकन नहीं भरा, इसलिए हेमंत निर्विरोध चुन लिए गए। हेमंत खंडेलवाल के पक्ष में यूं तो कई बातें हैं, लेकिन उसमे सबसे बड़ी बात उनका 'लो प्रोफाइल' होना है। वो खुद कभी लाइम लाइट में नहीं रहे, जबकि पार्टी के कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई, लेकिन विवादों से दूर रहे। इसके अलावा उनका उस वैश्य समुदाय से होना, जो भाजपा का कोर वोटर रहा है, भी महत्वपूर्ण है। अविभाजित मप्र में लखीराम अग्रवाल आखिरी नेता थे, जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे और वैश्य समुदाय से थे। तीसरा कारण हेमंत का भाजपा व संघ से पुराना जुड़ाव है। वो बैतूल के पूर्व भाजपा सांसद विजय खंडेलवाल के बेटे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे परिवारवाद के आईने में भी देख रहे हैं। हेमंत सुशिक्षित, कुशल व्यवसायी भी हैं। चौथे, वो अध्यक्ष पद के तमाम दूसरे दावेदारों की तुलना में युवा हैं। लिहाजा इसे पार्टी द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के रूप में भी देख जा रहा है। पहले वो सांसद रहे और अब विधायक हैं। हालांकि उन्हें चुनाव में एक बार हार का भी सामना करना पड़ा। हेमंत खंडेलवाल का कार्यकाल तीन साल का होगा। शुरू के डेढ़ साल उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। क्योंकि राज्य में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव 2027 में होने हैं। इसका लाभ यह है कि हेमंत संगठन को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकते हैं। उनकी असली परीक्षा 2027 में ही शुरू होगी, जब स्थानीय निकायों के बाद अगले विधानसभा और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। हेमंत खंडेलवाल को कमान सौंपे जाने से पार्टी को तबका खुश है, जो समर्पित ढंग से काम करता है। अलबत्ता प्रदेश अध्यक्ष पद के जो प्रबल दावेदार थे, उन्हें जरूर निराशा हाथ लगी है। इनमें पहला नाम पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का है, जो विधानसभा चुनाव में हारने के बाद किसी सम्मानित पुनर्वास की उम्मीद पाले हुए थे। अध्यक्ष के निर्वाचन के समय कतिपय बड़े नेताओं का नदारद रहना, इस बात का संकेत है कि हेमंत खंडेलवाल को सभी का विश्वास जीतने में काफी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यद्यपि मुख्यमंत्री और आलाकमान के वरदहस्त के चलते यह काम बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब निवर्तमान अध्यक्ष वी.डी.शर्मा के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में एक नाम उनका भी है। यह भी चर्चा थी कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। लेकिन कोई भी सूचना अधिकृत नहीं है। बहरहाल मप्र में भाजपा का संगठन शुरू से बहुत मजबूत रहा है। इसे और सुगठित और सक्रिय करने की जिम्मेदारी अब हेमंत खंडेलवाल पर है। साथ ही वो पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज भी उसी शिद्दत के साथ सुनेंगे, उनसे कार्यकर्ताओं की यह अपेक्षा बिल्कुल जायज है।

नजरिया

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आतंक पर दोहरे रवैये को लेकर राजनाथ का प्रहार

एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखस्तान के साथ हुई थी। हालांकि इसकी जड़ें 'शंघाई फाइव' से जुड़ी हैं, जो 1996 में चीन, रूस तथा तीन मध्य एशियाई गणराज्यों द्वारा सीमा सुरक्षा विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संवाद था परंतु बीते वर्षों में यह मंच धीरे-धीरे चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे का उपकरण बनता गया है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इस संगठन की चुप्पी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। इस बार के संयुक्त घोषणापत्र में ब्लूचिस्तान में कथित आतंकी घटनाओं का उल्लेख तो किया गया लेकिन पहलगाम जैसे जघन्य हमले को अनदेखा किया गया। भारत ने इसे पाकिस्तान के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता देने की साजिश बताया। ब्लूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां वहां के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ी हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत-प्रायोजित आतंकवाद कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है। चीन, जो सीपीईसी के माध्यम से ब्लूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के इन दावों का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि भारत को इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इंकार करना पड़ा।

चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की रक्षा मंत्रियों की बैठक इस बार भारत की आक्रामक और स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति की स्पष्ट साक्षी बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से जब यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उसमें आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है तो यह भारत का केवल एक औपचारिक विरोध नहीं था बल्कि भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं और कूटनीतिक दृढ़ता का स्पष्ट संकेत था। इस विरोध के जरिये उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल प्रतीकात्मक भाषणों और कूटनीतिक शिष्टाचारों से आगे बढ़ चुका है। भारत का संदेश दृढ़ है कि आतंकवाद को सामान्य नहीं माना जा सकता। भारत के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है।

भारत का यह कदम एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ खासकर उन देशों के लिए एक चेतावनी है, जो आतंकवाद को अपने रणनीतिक हितों के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उसके व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होती है। भारत का यह कदम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा तो है ही, चीन को भी यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने सुरक्षा हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह द्वारा की गई टिप्पणी कि 'आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है' और 'जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसे पनाह देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए', सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर संकेत था, हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। दक्षिण एशिया पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही दशकों से अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है और अब भारत इस खतरे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मुखरता से उजागर कर रहा है। भारत की इस बार की विशेष आपत्ति पहलगाम हमले को लेकर थी। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा की सहायक इकाई 'टीआरएफ' (द रेजिस्टेंस फ्रंट) द्वारा किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। यह हाल के वर्षों का सबसे भीषण आतंकी हमला था। भारत ने एससीओ के मसौदा दस्तावेज में इस हमले का उल्लेख नहीं किए जाने को गंभीर चूक नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति माना, जिसके पीछे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश साफ दिखती है। भारत का यह रुख अचानक नहीं बना बल्कि यह उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात करता रहा है और दोहरे मानदंडों को उजागर करता रहा है। इससे पहले भी भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल होने से इंकार कर दिया था क्योंकि उसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को शामिल किया गया था, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखस्तान के साथ हुई थी। हालांकि इसकी जड़ें 'शंघाई फाइव' से जुड़ी हैं, जो 1996 में चीन, रूस तथा तीन मध्य एशियाई गणराज्यों द्वारा सीमा सुरक्षा विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संवाद था परंतु बीते वर्षों में यह मंच धीरे-धीरे चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे का उपकरण बनता गया है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इस संगठन की चुप्पी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। इस बार के संयुक्त घोषणापत्र में ब्लूचिस्तान में कथित आतंकी घटनाओं का उल्लेख तो किया गया लेकिन पहलगाम जैसे जघन्य हमले को अनदेखा किया गया। भारत ने इसे पाकिस्तान के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता देने की साजिश बताया। ब्लूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां वहां के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ी हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत-प्रायोजित आतंकवाद कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है। चीन, जो सीपीईसी के माध्यम से ब्लूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के इन दावों का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि भारत को इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इन्कार करना पड़ा।

यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने एससीओ में ऐसा सख्त रुख अपनाया हो। बिश्केक (2019) और अस्ताना (2024) में भी भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि उस समय भारत ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे परंतु इस बार की परिस्थिति अलग थी। इस बार एक ऐसा हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई और उसे एससीओ की बैठक में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। भारत का यह कड़ा रुख केवल एससीओ तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। भारत का यह स्पष्ट संदेश था कि अब वह आतंकवाद के केंद्रों को उनकी सीमा में घुसकर खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह संदेश भी चीन और पाकिस्तान के लिए था कि भारत अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी आक्रामक कूटनीति अपना रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी स्पष्ट किया कि विश्वास-निर्माण तभी संभव है, जब चीन एलएसी पर अतिक्रमण की अपनी नीतियों को छोड़े और भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले। दोनों पक्षों ने सैन्य हॉटलाइन बहाल करने पर विचार किया लेकिन भारत ने यह भी जता दिया कि यह केवल दिखावटी बातचीत नहीं होनी चाहिए। भारत के इस सख्त रुख का एक और आयाम है, बिना उलझाव के संरेखण की नीति। भारत न किसी गुट का हिस्सा बनना चाहता है, न किसी के हितों का औजार। वह केवल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बहुपक्षीय मंचों पर भाग लेता है और किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता, जो उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या वैचारिक सिद्धांतों से टकराव रखता हो। यह नीति भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में भारत लगातार मांग करता रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ जैसे संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। चीन ने कई बार तकनीकी आपत्ति लगाकर इन प्रयासों को विफल किया है लेकिन भारत ने अपने प्रयासों को कभी धीमा नहीं किया।

एससीओ की इस बार की बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब 'सामूहिक सहमति' की कीमत पर अपने 'राष्ट्रीय हितों' की बलि नहीं चढ़ाएगा।

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को नाम लेकर नहीं लताड़ा जाएगा, तब तक कोई संयुक्त घोषणापत्र केवल कागज का एक टुकड़ा ही रहेगा। भारत के लिए यह रुख न केवल सम्मान का विषय है बल्कि वैश्विक मंचों पर उसकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाता है। आज भारत को वैश्विक मंचों पर सुना जा रहा है क्योंकि वह केवल बातें नहीं करता बल्कि अपने रुख पर अडिग भी रहता है। बहरहाल, अंतत:, भारत ने एससीओ के मंच से जो सख्त संदेश दिया है, वह केवल पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए भी है, जो आतंकवाद पर मौन साधे रहते हैं या अपने आर्थिक, कूटनीतिक हितों के कारण उसे नजरअंदाज करते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद अब केवल एक देश की समस्या नहीं है, यह वैश्विक मानवता के लिए खतरा है और इसके खिलाफ कूटनीतिक मंचों से लेकर वास्तविक जमीनी कार्रवाई तक निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

उपलब्धि

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक शोधार्थी हैं।

स्वप्न से यथार्थ तक- शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा

भारत की अंतरिक्ष गाथा में 25 जून 2025 का दिन स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ान भरकर देश को गर्व से भर दिया। यह केवल एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास, तकनीकी प्रगति और मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में निर्णायक कदम है। राकेश शर्मा के बाद पहली बार किसी भारतीय ने कक्षा पार की है, लेकिन इस बार भारत दर्शक नहीं, भागीदार है। यह यात्रा गगनयान मिशन की आधारशिला बनकर भारत के अंतरिक्ष स्वप्न को यथार्थ के करीब ले जाती है।

25 जून 2025 की दोपहर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और राष्ट्रीय गर्व का वह क्षण बन गई जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ओर ऐतिहासिक उड़ान भरी। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष आकांक्षाओं, उसकी रणनीतिक दृष्टि और तकनीकी आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा का जीवंत प्रतीक है। चार दशक पहले 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने जब 'सारे जहाँ से अच्छा' कहकर भारत को अंतरिक्ष में गौरव दिलाया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की अगली मानव उड़ान इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, इस नए युग की वैश्विक भू-राजनीति और निजी अंतरिक्ष भागीदारी के दौर में साकार होगी।

शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा Axiom-4 मिशन का हिस्सा है, जिसे NASA और SpaceX के सहयोग से अमेरिकी निजी कंपनी Axiom Space ने संचालित किया। भारत सरकार ने इस मिशन के तहत शुभांशु की अंतरिक्ष सीट के लिए लगभग रू. 548 करोड़ की राशि का निवेश किया। यह खर्च भले ही किसी को अत्यधिक प्रतीत हो, लेकिन इसके पीछे छिपे बहुआयामी लाभ, रणनीतिक दृष्टि और वैज्ञानिक महत्व को समझने पर यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष नीति का एक ठोस कदम है।

इस मिशन की महत्ता को केवल इस आधार पर नहीं आंका जा सकता कि भारत के एक और नागरिक ने पृथ्वी की कक्षा पार की, बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिशन भारत के बहुप्रतीक्षित गगनयान कार्यक्रम के लिए एक 'डेटा-संग्रहण' मिशन के रूप में काम करेगा। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग दो सप्ताह बिताएंगे और कुल 30 वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेंगे, जिनमें से आठ सीधे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। ये प्रयोग माइक्रोग्रैविटी में शारीरिक, जैविक, मानसिक और तकनीकी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे। इन आंकड़ों का विश्लेषण गगनयान मिशन की रूपरेखा तय करने में अत्यंत सहायक होगा।

गगनयान, भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी योजना 2027 तक इसे प्रक्षेपित करने की है। इस मिशन के लिए ISRO चार वायुसेना पायलटों को प्रशिक्षण दे रहा है, जिनमें से शुभांशु शुक्ला प्रमुख नाम हैं। उनकी यह उड़ान उन्हें उन परिस्थितियों का अनुभव देगी जो गगनयान मिशन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही, यह भारत को यह समझने का अवसर भी देगी कि अंतरिक्ष यात्रियों को किस प्रकार के शारीरिक, मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और उनके स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर अंतरिक्ष का क्या प्रभाव पड़ता है।

भारत ने इस उड़ान के लिए जिस निजी अमेरिकी कंपनी का सहारा लिया, वह इस बात का संकेतक है कि अब देश केवल पारंपरिक सरकारी ढांचे तक सीमित नहीं रहना चाहता। भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान को वैश्विक भागीदारी, वाणिज्यिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग के नए आयामों से जोड़कर देख रहा है। Axiom जैसी कंपनियाँ अब अंतरिक्ष में 'स्पेस टूरिज़्म' और अनुसंधान आधारित मिशनों के लिए निजी ग्राहकों को अवसर प्रदान कर रही हैं। भारत ने इस मौके को न केवल वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, बल्कि अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए चुना है।

शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक पहचान का प्रतीक बन सकती है। आज का भारत, जो वैश्विक मंचों पर अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी केवल 'अनुसरणकर्ता' की भूमिका में नहीं, बल्कि एक 'नेता' की भूमिका में दिखाई देना चाहता है। यह यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण की नई दौड़ में गंभीर खिलाड़ी के रूप में शामिल हो चुका है।

हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कमी यह भी रही कि भारत के अंतरिक्ष विभाग और ISRO ने इस मिशन के पीछे के उद्देश्यों और बजटीय औचित्य पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया। जब जनता का पैसा इस प्रकार के अभियानों में लगाया जाता है, तो पारदर्शिता अनिवार्य हो जाती है। रू. 548 करोड़ की यह राशि केवल एक सीट की नहीं, बल्कि उससे जुड़े प्रशिक्षण, बैकअप क्रू (प्रसांत नायर) की तैयारी और वैज्ञानिक उद्देश्य की संपूर्ण पैकेजिंग का हिस्सा है। फिर भी, सरकार को यह जिम्मेदारी निभानी होगी कि वह इस मिशन से प्राप्त होने वाले लाभों और उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करे ताकि आमजन का विश्वास और समर्थन बना रहे। शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा एक 'संवेदनशील प्रेरणा' का माध्यम भी बन सकती है। जिस प्रकार 1984 में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा ने स्कूल की किताबों में जगह बनाई, उसी प्रकार शुक्ला की यह यात्रा अब डिजिटल युग में युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर सकती है। आज की पीढ़ी जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और 24×7 न्यूज़ साइकिल में पली-बढ़ी है, वह अंतरिक्ष विज्ञान को केवल 'लैब का विषय' न मानकर एक 'जीवन विकल्प' के रूप में देख सकती है। ऐसे में शुभांशु का युवा, अनुशासित और प्रोफेशनल व्यक्तित्व भारत के अंतरिक्ष सपनों को लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

यह यात्रा भारत की अंतरिक्ष कूटनीति और वैश्विक स्थिति को भी नए आयाम देती है। अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग अब सीमित होता जा रहा है, जबकि चीन का 'तियांगोंग स्पेस स्टेशन' अंतरिक्ष में नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दे चुका है। ऐसे में भारत, जो अमेरिका के आर्टेमिस समझौते का सदस्य है और फ्रांस के साथ उपग्रह डेटा साझा करता है, अपनी एक संतुलित और रणनीतिक स्थिति बना सकता है। शुभांशु का यह मिशन भारत-अमेरिका साझेदारी को और भी मजबूत करता है, चाहे वह सैन्य, वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में हो। इस पूरे अभियान में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ISS (अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) को 2030 तक निष्क्रिय करने की योजना है। इसलिए भारत को ISS जैसी संरचनाओं का उपयोग करने का यह सीमित अवसर पूरी दक्षता से लेना होगा। अमेरिका की निजी कंपनियाँ जैसे Blue Origin भी भारत की गगनयान तकनीकों में रुचि दिखा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि यदि भारत इस दिशा में सफल रहा तो वह न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक साझेदारियों में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना, ISRO और उन सभी वैज्ञानिकों के लिए भी गौरव का क्षण है जिन्होंने दशकों से भारत के अंतरिक्ष स्वप्न को संजोया है। शुभांशु एक टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष प्रशिक्षण प्राप्त पायलट और गगनयान क्रू के सदस्य हैं। उनकी यह यात्रा भारत के लिए एक 'लर्निंग कर्व' है, जो व्यवहारिक अनुभव, वैज्ञानिक डेटा और रणनीतिक समझ के उस संकलन को प्रस्तुत करेगी जिससे गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके।इसके साथ ही, यह यात्रा भारत के उस परिवर्तन की घोषणा भी करती है जिसमें सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि, अभी इस दिशा में कई ढांचागत सुधार आवश्यक हैं। यदि भारत इस अवसर को केवल प्रयोग के रूप में न लेकर नीति के रूप में स्वीकार करता है, तो यह निश्चित है कि हम न केवल अपनी धरती से, बल्कि अपनी अंतरिक्ष उपस्थिति से भी विश्व को चौंका सकते हैं।

भारत की यह अंतरिक्ष यात्रा शुभांशु शुक्ला के साथ केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग तक सीमित नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना का विस्तार है। यह उस आत्मनिर्भर भारत की घोषणा है जो अब विश्व मंच पर आत्मविश्वास से अपने तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक शोध और मानवीय संसाधनों का प्रदर्शन करने में संकोच नहीं करता। शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान इस आत्मविश्वास की पुष्टि है कि भारत अब केवल उपग्रह प्रक्षेपण और प्रौद्योगिकी विकास तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को भी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस और व्यावहारिक कदम उठा चुका है। यह यात्रा एक ऐसी पीढ़ी को सामने ला रही है जिसके लिए विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में सीमित नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आज का युवा जो डिजिटल युग में बड़ा हुआ है, उसके लिए अंतरिक्ष एक दूर की कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावित पेशा, एक प्रेरणादायक सपना और एक वैज्ञानिक रोमांच बन सकता है। शुभांशु जैसे सुलभ, अनुशासित और सजीव उदाहरण उन्हें यह विश्वास देंगे कि यदि वे समर्पण, परिश्रम और देशभक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो अंतरिक्ष भी उनकी पहुँच से दूर नहीं।

भारत की शिक्षा नीति और विज्ञान संचार तंत्र को अब इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अंतरिक्ष शिक्षा को केवल विषय नहीं, बल्कि व्यवहारिक, प्रायोगिक और प्रोजेक्ट-आधारित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ISRO और अन्य संस्थानों को चाहिए कि वे शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा को शैक्षणिक सामग्री, वृत्तचित्रों, सार्वजनिक व्याख्यानों और संवाद श्रृंखलाओं के माध्यम से समाज तक पहुँचाएं। यह वैज्ञानिक चेतना और देशप्रेम के सम्मिलन का श्रेष्ठ अवसर है। इसके साथ ही, यह समय नीति निर्माताओं के लिए भी आत्ममंथन का है। भारत का अंतरिक्ष बजट अब भी विश्व के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में सीमित है। जबकि भारत ने चंद्रयान, मंगलयान, और अब मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वहीं इस क्षेत्र को और अधिक संस्थागत निवेश, वैज्ञानिक स्वतंत्रता, नवाचार प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है। IN-SPACe जैसे संस्थानों की भूमिका, निजी उद्योगों की सक्रियता, और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के स्पष्ट रोडमैप से ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत 2030 के बाद भी अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रख सके।

शुभांशु शुक्ला की यात्रा भारत को यह सिखा रही है कि भविष्य उन्हीं देशों का होगा जो विज्ञान में निवेश करेंगे, तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देंगे और अपनी युवा पीढ़ी को सपने देखने, उन्हें पाने और उन्हें पारिभाषित करने की स्वतंत्रता देंगे। यह यात्रा केवल एक अंतरिक्ष यान की नहीं, बल्कि उस चेतना की उड़ान है जो आने वाले भारत की रचना करेगी। शुभांशु की यात्रा का अंत भले ही कुछ सप्ताहों में होगा, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले दशकों तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षा, युवा प्रेरणा और वैश्विक कूटनीति में महसूस किया जाएगा। अगर गगनयान समय से उड़ान भरता है और वह सफल रहता है, तो एक दिन भारत की पीढ़ियाँ यह कहेंगी कि जब शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी, तभी भारत के अंतरिक्ष युग की दूसरी क्रांति का आरंभ हुआ था।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सफेद कबूतरों से खतरा

हुजूर, सारी दिक्क़त सफ़ेद कबूतरों से है। इन्हें लत पड़ी हुई है प्रेम सन्देश इधर से उधर करने की। लोग भी नासमझ हैं, जब भी ये पंख खोलते हैं ऐसा माना जाता है कि शांति का पैगाम फैला रहे हैं! हमारे खिलाफ़ माहौल भी बनाते हैं। इन पर लगाम नहीं कसी गई या इनके पर नहीं काटे गए तो देख लेना एक दिन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। कौवे ने बाज-महाराज से कहा।

बाज को सुबह से कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी, वह तैश में आ गया - ऐसे कैसे धर्म खतरे में पड़ जाएगा! धर्म है तो जंगल है, जंगल है तो जंगली हैं और जंगली है तो हमारी सत्ता है। धर्म को बचाना ही सत्ता को बचाना है।... तुम कौवे होकर इतना नहीं समझते हो! समझता हूँ हुजूर, इसीलिए तो सफेद कबूतरों की हिमाकत बता रहा हूं। कौवे आपके वफादार हैं। आप हैं तो हमारा अस्तित्व है। आप से बचा खाकर ही हमारी कौम जिंदा रहती है।

काले कबूतर क्या करते हैं!! उनकी संख्या तो काफी ज्यादा है। जंगल में बिखरा दाना ज्यादातर वही खा जाते हैं। उन्हें विकल्प देना चाहिए। 'बाज ने कहा।

मुझे अफसोस से बाज महाराज। काले कबूतर तो जंगली ही कहलाते हैं। प्रेम और शांति के प्रति उनमें संवेदन नहीं होती है। वे कितना ही पर फैला लें लेकिन लोगों में उनके प्रति भरोसा पैदा नहीं होता है। तुम भी तो कौवे हो, और किसी लायक नहीं हो। फिर भी जंगल में जमे हुए हो या नहीं? श्राद्ध पक्ष में बस्तियों में जाते हो और पूजे भी जाते हो या नहीं ? काले कबूतरों को अपने साथ रखा करो। कुछ संस्कार दो उन्हें, सत्ता-भक्ति सिखाओ। उन्हें समझाओ कि भक्ति में शक्ति होती है।' बाज ने आदेशनुमा सुझाव दिया। कौवे ने सिर झुकाते हुए कहा - क्षमा करें महाराज, कौवा बिरादरी उच्च है। आप सरकार के साथ उठना बैठना और खाना पीना है हमारी बिरादरी का। हम उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते।'

तो फिर सफेद कबूतरों की समस्या का क्या होगा! कैसे रोकेंगे इन्हें?

इसके दो तरीके हैं महाराज। पहले इन्हें जंगल-द्रोही घोषित करके मार खाया जाए। दूसरा उन्हें पुरस्कार और सम्मान देकर महान बना दिया जाए। एक बार किसी को सत्ता से महानता का प्रमाण पत्र मिल जाए तो उसका रंग बदल जाता है।

क्या पुरस्कृत कबूतर सफेद से काले हो जाते हैं!!

रहते तो सफेद ही हैं महाराज, लेकिन उन्हें काला दिखाना बंद हो जाता है।

विश्व रंग

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

नाटो को नयी गिज़ा मिली

हेग में हुआ नाटो का शिखर सम्मेलन अपने आशय से अमेरिका के विस्तारवाद की पुष्टि करता है और अमेरिका की सुविचारित और नियोजित भूराजनीतिक और सामरिक व्यूह रचना को दर्शाता है। सम्मेलन में करीब डेढ़ दर्जन गैर नाटो देशों को अमांत्रित करने के पीछे यही रणनीति काम कर रही है। यह अकारण नहीं है कि मक्ट्रनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोव्स्का-दाव्कोवा ने अपने संबोधन में योरोपीय यूनियन के विस्तार की प्रक्रिया को रोकने की बात कही।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानि नाटो का चौतीसवां शिखर सम्मेलन 24 और 25 जून को नीदरलैंड में हेग में सकुशल संपन्न हो गया। संगठन में अतीत में पड़ी दरारों से यह आशंका थी कि नाटो में मतभेद उभर सकते हैं अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल और जिद्दी रवैये से सम्मेलन किसी सर्वसम्मति या सामूहिक फैसले पर नहीं पहुंचे, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। उलटे विभिन्न मुद्दों पर शरीक राष्ट्रों में मतैक्य ने संगठन में अमेरिका की नाभिकीय सत्ता और वर्चस्व पर मोहर लगा दी, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप की बांछे खिलना स्वाभाविक है। कह सकते हैं कि हेग सम्मेलन से नाटो को नयी गिज़ा मिली। सम्मेलन सदस्य देशों के बीच मतभेदों को रफू करने में सफल रहा और उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि संगठन आगामी समय में रूस की मुश्कें कसने की कवायद में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगा।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन चार अप्रैल, सन 1949 को वाशिंगटन-संधि के तहत वाशिंगटन डीसी में स्थापित हुआ था। इसके जरिये अमेरिका विश्वयुद्धोत्तर दौर में योरोपीय शक्तियों के साथ सामूहिक रक्षा-व्यवस्था को अमली जामा पहनाना चाहता था और उसका मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना। पूर्वी योरोप का कम्युनिस्ट ब्लॉक उसके लिये चिंता का विषय था, लिहाजा प्रमुख योरोपीय राष्ट्रों को इसके तंतु-जाल में समेटा गया। इसके मसौदे के मुख्य लेखक थे जॉन डि हिकर्सन। शुरू में इसके सदस्य थे बेल्जियम, कनाडा, डेन्मार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, अमेरिका, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। संगठन की स्थापना को पश्चिमी योरोप पर सोवियत रूस के संभावित आक्रमण की पेशबंदी के तौर पर देखा गया। सोवियत संघ की नीतियों ने यूं भी एंग्लो-अमेरिकी धुरी और अनेक योरोपीय देशों की धुकधुकी बढ़ा दी थी। बहरहाल, समय के साथ इसकी कैनोपी फैलती गयी और सन् 1952 में ग्रीस और तुर्की इससे जुड़ गये। सोवियत संघ के विघटन के बाद तो इस छतरी के तले आने वाले राष्ट्रों की कतार लग गयी और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्वीडन, फिनलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवोनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, उत्तरी मैसीडोनिया इसमें सम्मिलित हो गये। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद यह स्थिति अमेरिका के लिये बड़ी फायदेमंद थी। बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ द्वारा प्रायोजित और गठित वार्सा-पैक्ट के अनेक देशों ने नाटों का दामन थाम लिया था। अमेरिका अपनी युक्तियों से योरोपीय देशों में रूस का 'हौव्वा' खड़ा करने में सफल रहा और उक्राइना के जरिये उसे रूस को छेंकने का बड़ा अवसर भी मिला गया।

हेग में हुआ नाटो का शिखर सम्मेलन अपने आशय से अमेरिका के विस्तारवाद की पुष्टि करता है और अमेरिका की सुविचारित और नियोजित भूराजनीतिक और सामरिक व्यूह रचना को दर्शाता है। सम्मेलन में करीब डेढ़ दर्जन गैर नाटो देशों को आमंत्रित करने के पीछे यही रणनीति काम कर रही है। यह अकारण नहीं है कि मक्ट्रनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोव्स्का-दाव्कोवा ने अपने संबोधन में योरोपीय यूनियन के विस्तार की प्रक्रिया को रोकने की बात कही। गौरतलब है कि इसमें योरोपीय यूनियन और सिंगापुर, थाइलैंड, उक्राइना, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, आर्मीनिया, फिलिपींस, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैंड, जापान, जार्डन, न्यूजीलैंड और अजरबैजान आदि देश भी आमंत्रित थे। जाहिर है कि अमेरिका रूस-चीन धुरी की वैश्विक घेराबंदी करना चाहता है। अमेरिका के लिये नाटो की अहमियत का पता इससे चलता है कि इसके ब्रूसेल्स में तीन असाधारण सम्मेलन हो चुके हैं और उक्राइना पर रूसी हमले के बाद सन 2022 में इसका आभासी-सम्मेलन आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि नाटो का मुख्यालय ब्रूसेल्स में स्थित है।

नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कोसोवो, बोस्निया, हर्जेगोविना में नाटो की सेनाएं उपस्थित रहेंगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी कोसोवो की बात की और पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में तुर्की-सैनिकों की मौजूदगी को सही ठहराया। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक हुये और उन्होंने भारत-पाक और कोसावो-सार्बिया जग में अमेरिकी दखल के साथ-साथ कांगो और रवांडा में संघर्ष का जिक्र किया। ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि सदस्य राष्ट्र उनके अंतिमेत्थम को मानकर सन 2025 तक अपने जीडीपी का पांच प्रतिशत अंश रक्षा-व्यवस्था में निवेश करने को तैयार हो गये। इसमें 3.5 प्रतिशत राशि मित्र-सेनाओं की रक्षा-आवश्यकताओं और शेष 1.5 फीसद रकम बुनियादी ढाँचे पर खर्च करने पर रजामंदी हुई।

हेग-सम्मेलन के जरिये अमेरिका को एक बड़ी कामयाबी यह मिली कि सभी सदस्यों ने उक्राइना को अटूट और दीर्घकालिक समर्थन के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। रूस के खिलाफ संघर्ष के लिये उसे सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण पर सभी राष्ट्र एकमत दिखे। दस साल पहले के सुरक्षा पर दो प्रतिशत के खर्च को देखें तो उसमें एक-मुश्त ढाई गुना वृद्धि नाटो की आड़ में अमेरिका के सामरिक मंसूबों की अभिव्यक्ति है। वार्ता में नाटो के रूपांतरण की बात भी कही गयी और परस्पर साझेदारी और गठबंधन की मजबूती पर जोर दिया गया।

गैर नाटों देशों से साझेदारी के साथ ही नये सदस्यों की भर्ती की बात भी कही गयी। रूस-चीन-ईरान धुरी का मुद्दा भी उठा और नाटो-सदस्यों ने एकजुटता का संकल्प लिया। साफ दिखा कि नाटो-बिरादरी ने पुरानी कटुता को भुला दिया है। नीदरलैंड के साम्राज्ञी और सम्राट के रात्रिभोज ने हेग सम्मेलन के वातावरण को खुशनुमा बना दिया। तय हुआ कि अगला सम्मेलन इस्तांबूल (तुर्किये) और तदंतर तिराना (अल्बानिया) में होगा। नाटो को मजबूती और विस्तार से अमेरिका के वर्चस्व के पाये बिलाशक मजबूत होते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि युद्ध, भुखमरी, जलवायु-परिवर्तन और असमानता से ग्रस्त विश्व में शांतिकामी शक्तियां निरंतर कमजोर पड़ती जा रही है।

अंकुरण

सत्येन्द्र पाण्डेय

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

कोई भी मुश्किल रोक न पाई शबाना आज़मी का हौसला

शबाना आज़मी से पहली मुलाकात जबलपुर में हुई, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के एक अभियान के सिलसिले में। जाहिर है, उनका नाम सबके लिए आकर्षण और कौतुहल का विषय था। इसका कारण हिन्दी फिल्मों की एक बड़ी सशक्त अभिनेत्री के नाम से उनके नाम की समानता होना था। इसके जवाब में बाद में उन्होंने बताया भी था कि पहली बात तो यह है कि उनके पिता उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ताल्लुक रखते थे और वे खुद कैफ़ी आज़मी की शायरी के प्रशंसक थे। वे कैफ़ी साहब की बेटी शबाना आज़मी की अदाकारी से भी बहुत प्रभावित थे और इसलिए अपनी बेटी का नाम उन्होंने शबाना आज़मी रखा।

शबाना आज़मी छिंदवाड़ा में रहती हैं और सत्यकाम जन कल्याण समिति के माध्यम से समाज के वंचित तबकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। वे खुद एक सशक्त लीडर हैं और समाज के बदलाव में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो दशकों से पूरे समर्पण के साथ जमीनी स्तर पर मजबूती से अपना काम करने में जुटी हुई हैं। इसलिए जब हम लोग अंकुरण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं की तलाश कर रहे थे जिनका नेतृत्व समाज के वंचित समुदाय अर्थात् दलित, आदिवासी अथवा अल्पसंख्यक तबकों से आने वाली महिलाओं के द्वारा किया जा रहा हो,तो स्वाभावित ही था कि मुझे शबाना आज़मी की याद आई। बहुत सालों से उनके साथ कोई संपर्क नहीं था और मुझे लगता था कि बहुत संभव हो वे मुझे भूल भी गई हों। आखिर बहुत कम मुलाकातें थीं और पिछले कुछ सालों से तो संपर्क भी नहीं था। और इस बीच कोरोना का दौर दुनिया में आ ही चुका था जिसने हम सबके जीवन को उथल पुथल कर दिया था। शबाना आज़मी भी इसका अपवाद नहीं थीं।

बहरहाल, मैंने अपने कुछ मित्रों से संपर्क किया जो उनको जानते थे। संपर्क सूत्र मिला और उनसे अंकुरण के साथ जुड़ने का आग्रह किया गया। वे अपनी संस्था के माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बनी, यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और उत्साह की बात थी। इस कार्यक्रम में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए भी।

अंकुरण के तीन सालों के दौरान उनके साथ अनेक खट्टे मीठे अनुभव हुए, असहमतियां भी होती रहीं लेकिन निजी और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर सकारात्मकता के साथ समाज की बेहतरी के लिए काम करने का अनुभव भी हासिल हुआ। उनका काम छिंदवाडा जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचलों में जैसे कि तामिया, पातालकोट और हर्रई इत्यादि में सैकड़ों गांवों में फैला हुआ है। अनेक बार उनके काम का विस्तार चिंता में डालता है कि क्या इतने कम संसाधन और क्षमताओं के साथ इतने बड़े क्षेत्र में इतनी अधिक तादाद में महिलाओं के साथ काम करना उचित होगा? लेकिन वे हार नहीं मानती बल्कि इसे चुनौती की तरह लेती हैं और काम को आगे बढाने की योजना में जुटी रहती हैं। और इसी का परिणाम है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं के जीवन में बेहतरी और खुशहाली लाई है।

लेकिन क्या इतना आसन है शबाना आज़मी हो जाना? मेरा जवाब है- बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने जीवन के हरेक मोड़ पर कठिन समस्याओं का सामना किया और प्रत्येक समस्या को उन्होंने एक चुनौती के रूप में ग्रहण किया और उससे घबराकर चुप बैठने की बजाय उन्होंने डटकर उसका सामना किया। यह लड़ाई केवल बाहर की दुनिया से नहीं थी बल्कि अपने अन्दर भी वे इस लड़ाई को लगातार लडती रही हैं। यही कारण है कि वे अपने व्यक्तित्व को इतना आत्मनिर्भर और ठोस बना सकने में सफल हुई हैं।

उनका जन्म एक परंपरागत मुस्लिम पिछड़ा वर्ग परिवार में हुआ था जिसे पसमांदा कहा जाता है। उनके पिता ने बहुत मुश्किलों के बावजूद अपना एक मुकाम तैयार किया था जिसे वे अपने बच्चों को विरासत में सौंपना चाहते थे और वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें-लिखें और बेहतर जीवन हासिल करें। जाहिर है, समाज को पिछड़ा बनाये रखने में कुछ लोगों का स्वार्थ निहित होता है और वे लड़कियों के आत्मनिर्भर हो जाने को पसंद नहीं करते हैं। जाति-धर्म की असमानताओं के बावजूद समाज को पीछे ले जाने की सोच रखने वाले लोगों की किसी फिरके में कोई कमी नहीं है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा पर पाबंदियां लगे जाती हैं। यदि परिवार इन पाबंदियों को नहीं मानता तो उसे समाज के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। लेकिन शबाना और उनके परिवार ने इस गुस्से की परवाह नहीं की। शुरू में नुकसान भी उठाये लेकिन बाद में सामान्य होता गया लेकिन इतना भी समान्य कहाँ होना था?

पढ़ाई पूरी करने के बाद शबाना आज़मी ने तय किया कि वे समाज सेवा के काम में आएँगी और अपने जैसी लड़कियों और महिलाओं के जीवन में बेहतरी लाने के लिए काम करेंगी। यह परिवार के लिए भी मुश्किल समय था। क्योंकि पढ़-लिखकर लड़की कोई आसान सरकारी नौकरी कर ले तो फिर भी बेहतर लेकिन यह लड़की तो दूर देहातों में जाकर गरीबों और आदिवासियों के साथ काम करने में जीवन की सफलता देख रही है। यह एक दूसरा संघर्ष था जिसे शबाना ने पार किया।

वे एक देशव्यापी नेटवर्क इंसाफ के साथ जुड़ गईं। 2002 में उन्हें इन्साफ का मध्यप्रदेश इकाई का संयोजक चुना गया और बाद में वे उसकी राष्ट्रीय संयोजक बनाई गईं। आदिवासियों खासकर महिलाओं के लिए जल, जंगल और जमीन पर हकदारी के सवाल पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2006 में उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से सत्यकाम जन कल्याण समिति का गठन किया। सत्यकाम ने मुख्य रूप से भरिया आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। भरिया मध्य प्रदेश की उन तीन आदिम जनजातियों में शामिल है जिनका शिक्षा और रोजगार आदि में बहुत कम दकाह्ल मन जाता है और इसलिए इनके संरक्षण हेतु राज्य से विशेष प्रयास किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अन्य दो जनजातियाँ हैं- बैगा और सहरिया।

विगत दो दशकों में शबाना आज़मी और सत्यकाम जन कल्याण समिति ने आदिवासी महिलाओं को आजीविका और शिक्षा से जोड़ने, घरेलु हिंसा कम करने और हिंसा के मुद्दे पर समझ बनाने हेतु अथक प्रयास किये हैं। इस दौरान वे एक सशक्त सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित हुई हैं लेकिन वे यह समझती हैं कि एक व्यक्ति के सशक्तिकरण से समाज में बदलाव नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपने जैसी महिला लीडर्स की एक पूरी पीढ़ी तैयार की है जिनकी संख्या सैकड़ों में है और शबाना आज़मी को विश्वास है कि ये सब महिलाएं और किशोरियां मिलकर समाज को महिलाओं के लिए हिंसामुक्त, शिक्षा और आजीविका के माध्यम से गरिमामय बनाने में सफल होंगी।

सामयिक

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

राजनीतिक शर्म निरपेक्षता और बकवासवाद

बीते कुछ वर्षों से यह हल्ला मचा हुआ है कि अम्बेडकर जी का संविधान ख़तरे में है और उसे बचाये रखना ज़रूरी है। नेता संविधान की प्रति लहराते घूम रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लगता है कि वे संविधान को पढ़ नहीं रहे। उसे लिखते समय जो बहसें हुईं और जो प्रश्न उठाये गये उन पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। कोई कह रहा है कि संविधान से वे दो शब्द - धर्म निरपेक्ष और समाजवाद - हटा दो और कोई कह रहा है कि इन शब्दों को नहीं हटाया जा सकता। कोई कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में लिखे चार शब्द - स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता ही पर्याप्त हैं। संविधान में लिखे इन शब्दों पर मचे हो-हल्ले में किसी भी राजनीतिक दल का देश के बहुरंगी जीवन के प्रति समर्पण नहीं, राजनीतिक सत्ता पाने का लोभ ही अधिक झलक रहा है और कोई भी दल अम्बेडकर जी की चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दे रहा है।

कुछ दिनों से यूट्यूब के संग्रह में संचित श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन रहा हूँ। उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया है कि एक समय अपराध करने वाले लोग राजनीतिक नेताओं से मदद माँगते थे। फिर ऐसा समय आया कि नेता ही अपराधियों से मदद माँगने लगे। फिर अपराधियों को ही यह लगने लगा कि जब हमारी मदद के बिना नेताओं का काम नहीं चलता तो हम खुद ही राजनीति के क्षेत्र में आ जायें। प्रत्यक्ष अनुभव से कही गयी अटल जी की यह बात आज कितनी सच जान पड़ती है। पर हमारे राजनीतिक दल इस सच्चाई को झुठलाकर संविधान की रक्षा करने की डींगें मार रहे हैं। पता नहीं, हमें कब अपने इन राजनीतिक दलों की शर्म निरपेक्षता और बकवासवाद से छुटकारा मिलेगा?

बीते कुछ वर्षों से यह हल्ला मचा हुआ है कि अम्बेडकर जी का संविधान ख़तरे में है और उसे बचाये रखना ज़रूरी है। नेता संविधान की प्रति लहराते घूम रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लगता है कि वे संविधान को पढ़ नहीं रहे। उसे लिखते समय जो बहसें हुईं और जो प्रश्न उठाये गये उन पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। कोई कह रहा है कि संविधान से वे दो शब्द - धर्म निरपेक्ष और समाजवाद - हटा दो और कोई कह रहा है कि इन शब्दों को नहीं हटाया जा सकता। कोई कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में लिखे चार शब्द.....स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता ही पर्याप्त हैं। संविधान में लिखे इन शब्दों पर मचे हो-हल्ले में किसी भी राजनीतिक दल का देश के बहुरंगी जीवन के प्रति समर्पण नहीं, राजनीतिक सत्ता पाने का लोभ ही अधिक झलक रहा है और कोई भी दल अम्बेडकर जी की चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दे रहा है।

अम्बेडकर की दृष्टि में बंधुता का अर्थ है... सभी भारतीयों के भाईचारे और एक होने की भावना। यही बात हमारे सामाजिक जीवन को अखण्डता प्रदान कर सकती है और यह बहुत ही कठिन काम हमें कर दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि... 26 जनवरी 1950 से हम कई अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता प्राप्त होगी पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में नहीं होगी। हम 'एक व्यक्ति एक वोट' को मान्यता देते रहेंगे पर हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण 'एक व्यक्ति एक मूल्य' के सिद्धांत को नकारते रहेंगे।

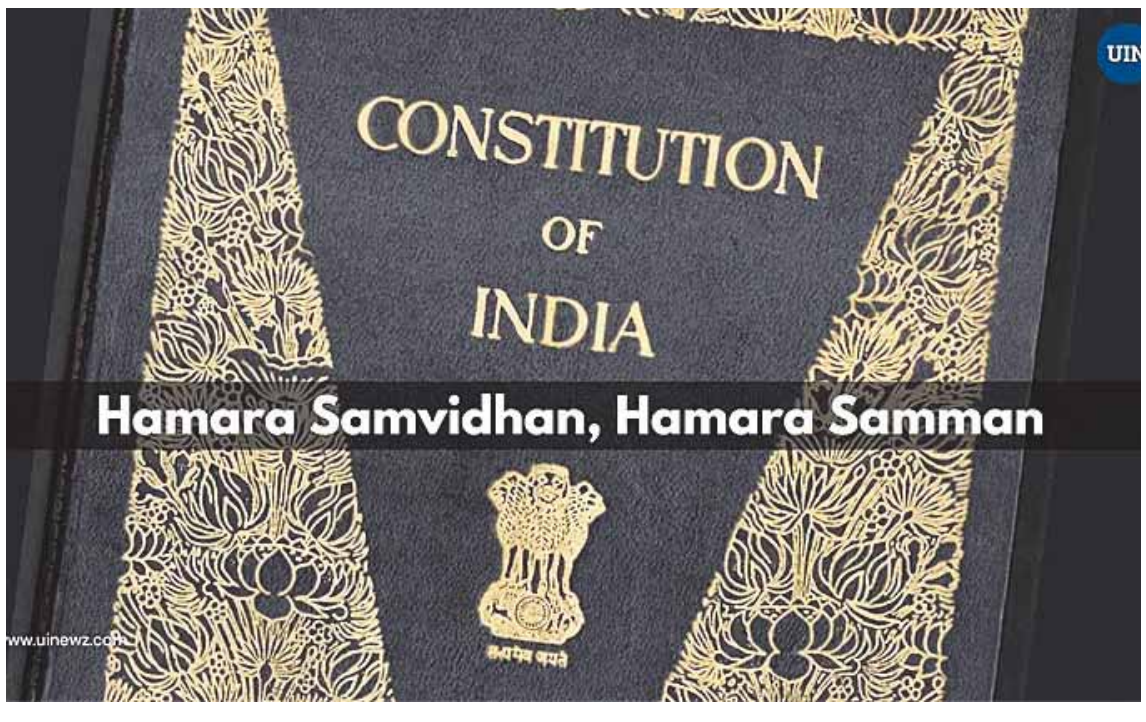

अम्बेडकर की यह आशंका अब तक सही साबित होती आयी है। धर्म जाति संप्रदाय के भेदभावों से ग्रस्त समाज में आर्थिक न्याय भी तब तक काफी नहीं है जब तक उसके साथ सामाजिक न्याय जुड़ा हुआ न हो। संविधान की रचना करते हुए वे महसूस कर रहे थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाये, खराब निकलें तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर, संविधान में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हों, यदि उसे अमल में लाने वाले ईमानदार हों तो संविधान अच्छा साबित होगा।

अम्बेडकर कहते हैं कि - किसी संविधान पर अमल उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। वह तो केवल विधायिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान ही कर सकता है। इन अंगों का नीतिपूर्वक संचालन जनता और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बने राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। अम्बेडकर गहरे सोच में डूबकर यह भी रेखांकित करते हैं कि -अभी से यह कौन कह सकता है कि आने वाले समय में भारत के लोगों और राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा?

अम्बेडकर को जो शंका थी वह सही साबित हो रही है। वे देख पा रहे थे कि हमारी अतीतजीवी स्मृति में जाति और संप्रदायों के रूप में पुराने शत्रु तो बने ही रहेंगे। परस्पर विरोधी विचार रखने वाले राजनीतिक दल भी बना लिये जायेंगे। ऐसी हालत में क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? आज हम देख ही रहे हैं कि जात-पांत और पंथ की सीमाओं में जकड़ी राजनीतिक ज़मीन पर अंध सत्तावाद की धूल उड़ रही है और जिसकी धुंध में देश अदृश्य हो रहा है।

अम्बेडकर चेतावनी दे गये हैं कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से बड़ा मानेंगे तो हमारी स्वतंत्रता भयानक खतरे में पड़ जायेगी और संभवत: हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। वे आह्वान करते रहे हैं कि सभी देशवासियों को इस संभावित घटना का प्रतिकार करते रहना चाहिए। अम्बेडकर जी की बात सुनकर अनुभव होता है कि मतांध कट्टरता का प्रतिकार करना हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। जैसे हम रोज़ अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते हैं ठीक वैसे ही देश के लोकतांत्रिक शरीर की रक्षा भी हमें प्रतिदिन करना होगी। लोकतंत्र की रक्षा नेताओं और नागरिकों के बीच बंधुता के मूल्य को बनाये रखने से ही होगी। यह राष्ट्र की अस्मिता के लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान में लिखे शब्दों को बदलने से कुछ नहीं होगा।

एक वर्ष से फरार हत्या के दो ईनामी आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। पुलिस ने एक वर्ष से फरार हत्या के दो ईनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 जून को हरिओम पिता धनराज यादव, निवासी टीकाबर्री, थाना बोरदेही की हत्या की सूचना पर थाना बोरदेही में धारा 302, 323, 34 भा.दं.वि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में नामजद आरोपी गोकुल पिता देवा यदुवंशी और 2. सुरेश उर्फ राजू पिता प्रेमलाल यदुवंशी, दोनों निवासी टीकाबर्री, थाना बोरदेही वारदात के दिन से ही फरार थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों आरोपियों पर 5,000-5,000 के ईनाम की उद्घोषणा की गई थी। 30 जून को बोरदेही पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें उपजेल मुलताई भेजा गया है। इस कार्रवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम बट्टी, सउनि कमलसिंह मेहर, सउनि विवेक मेहरा, प्र.आर. अनिल धुर्वे, प्र.आर. सुनील पन्द्राम, आरक्षक विशाल चौरसिया, आरक्षक रोहन उईके, आरक्षक राधेश्याम कुमरे, आरक्षक मनोज पाल, आरक्षक रामकिशन नागोतिया, आरक्षक किशोर साहू, महिला आरक्षक आरती पवार टीम की सराहनीय भूमिका रही।

बस ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

40 से ज्यादा यात्रियों की बची जान

बैतूल। बैतूल-भोपाल नेशनल हाईवे पर उड़दन गांव के पास नागपुर जा रही डिस्ट्रिक्ट बस को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक कट मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कंटेनर की इस हरकत से बस पूरी तरह संतुलन खो सकती थी, लेकिन बस चालक ने बिना घबराए त्वरित निर्णय लेते हुए बस को सडक़ के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ा दिया। यह कदम जोखिम भरा जरूर था, लेकिन इसी के चलते बस कंटेनर की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। जब यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जो सुरक्षित बच निकले। घटना के बाद सभी यात्रियों ने चालक की हिम्मत और समझदारी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वह कुछ सेकंड भी देरी करता, तो आज कोई बड़ा अनर्थ हो सकता था। फिलहाल किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। कंटेनर चालक की पहचान की जा रही है।

ई अटेंडेंस सभी विभागों पर लागू हो

मप्र शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। मप्र शिक्षक संघ द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के नाम से जिला प्रशासन को मप्र मे शुरू हो रही ई अटेंडेंस पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप गीते ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व मे भी ई अटेंडेंस प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, परंतु यह व्यवस्था अव्यवहारिक और शिक्षक समाज को जन सामान्य के बीच अच्छी छवि नही बनाती है एवं शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को करने वालो के लिए अपमानजनक व्यवस्था है। सचिव मदन यादव ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस व्यवस्था को अपमानजनक व्यवस्था बताकर बंद कर दिया था एवं पुन- इस व्यवस्था को शुरू नहीं करने का आश्वासन दिया था। जिला संगठन मंत्री बीआर ठाकरे ने बताया कि वर्तमान मे इस ई अटेंडेंस के विरोध मे प्रदेश के शिक्षकों मे रोष है। यह व्यवस्था पूर्णत- मोबाइल पर आधारित है जो स्कूलों मे मोबाइल के उपयोग को बढ़ावा देती है। मोबाइल खराब होने, नेटवर्क नहीं मिलने, गुमने या घर पर भूल जाने से इस व्यवस्था से परेशानी होगी जिसमे शिक्षक भौतिक रूप से दिनभर स्कूल मे उपस्थित रहेगा परंतु मोबाइल के अभाव मे अनुपस्थित माना जायेगा। शिक्षक की निगरानी अवश्य हो परंतु ऐसी हो कि मानवीय गरिमा का ह्रास न हो। अगर हम वास्तव मे शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहते है तो विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाये रखना होगा। लेकिन अनुशासन की कीमत संवेदनाओं की अनदेखी करके नहीं चुकानी चाहिए।

ताप्ती जन्मोत्सव पर ताप्ती तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां ताप्ती के दर्शन

बैतूल /मुलताई। मां ताप्ती जन्मोत्सव पर ताप्ती तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही ताप्ती तट पर पूजन पाठ और ताप्ती स्नान करने वालों का जमावडा होना प्रारंभ हो गया था। मां ताप्ती के जयकारे लगाते हुए ताप्ती भक्त हाथों में श्रद्धा सुमन थाल लिए मन में मां ताप्ती दर्शन की आस लिए बड़ी संख्या में ताप्ती परिक्रमा क्षेत्र पहुंचे। दोपहर को विशाल नदी पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की शोभायात्रा निकाली गई जो की आकर्षण का केंद्र रही। शाम होते तक ताप्ती परिक्रमा क्षेत्र में चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने एवं ताप्ती दर्शन करने का अनुमान है। भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गढेकर एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताप्ती मंदिर पहुंचकर मां ताप्ती की पूजा अर्चना की उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। सुबह 5 बजे से ही ताप्ती जन्मोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे सुबह 5 बजे विशेष पूजा अर्चना के साथ ही दुग्ध अभिषेक किया गया इसके उपरांत नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर ने दोनों ताप्ती मंदिरों में पहुंचकर मां ताप्ती का दुग्ध अभिषेक किया, माता की ओटी भरी और मां ताप्ती का सिंगार किया। बीते एक सप्ताह से ताप्ती तट गायत्री मंदिर में कथावाचक वैष्णवाचार्य डॉ विश्वामित्र शरण द्वारा की जा रही ताप्ती कथा का आज सप्त ऋषि टापू पर हवन पूर्ण आहुति के साथ संपूर्ण समापन कर दिया गया।

मां ताप्ती को चढ़ाई 251 मीटर लंबी चुनरी: प्रतिवर्ष अनुसार ताप्ती सेवा मंडल द्वारा 251 मीटर लंबी विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई जिसमें पूर्व मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड अध्यक्ष हेमंत विजय राव देशमुख, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर सहित सेवा मंडल के सदस्य एवं महिलाओं ने भाग लिया। ताप्ती मंदिर से प्रारंभ होकर परिक्रमा करते हुए यह चुनरी यात्रा ताप्ती आरती घाट पहुंची जहां मां ताप्ती की आरती पूजन के उपरांत नाव के माध्यम से मा ताप्ती को 251 मीटर लंबी चुनरी अर्पण की गई।

महिला चोरों ने बताई हाथ की सफाई: ताप्ती जन्मोत्सव के चलते परिक्रमा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए थे। जगह-जगह महिला एवं पुलिस अधिकारी भी तैनात किए थे, किंतु इन सब के बावजूद सलवार सूट पहने 3 महिलाओं द्वारा कुछ महिलाओं के जेवर पर हाथ साफ करने की खबर है। इन महिलाओं से सावधान रहने के लिए नगर पालिका निरंतर अलाउंस करती रही। गजानन मंदिर के सामने नगरपालिका, पुलिस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों का कंट्रोल रूम बनाया गया था ताकि जन्मोत्सव मे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। नगर के मध्य के संपूर्ण भाग को बैरिकेडिंग कर दो पहिया से लेकर सभी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

300 से अधिक स्थानों पर लगे भंडारा प्रसादी स्टॉल

ताप्ती जन्मोत्सव पर संपूर्ण पवित्र नगरी धर्म नगरी में परिवर्तित हो गई है। मंदिरों मे विशेष साज-सज्जा की गई है। इस वर्ष ताप्ती जन्मोत्सव में पिछले साल की तुलना में जहां लोगों में अधिक जागरूकता देखी गई, वहीं श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा गया। ताप्ती प्रथम पुलिया से लेकर परमंडल जोड़ तक 50 से भी अधिक स्थानों पर जगह-जगह भंडारा प्रसादी के स्टॉल लगाए गए थे। बस स्टैंड पर विभिन्न संगठनों द्वारा 10 से अधिक स्थानों पर भंडारा प्रसादी वितरण की गई। इसके अलावा थाने के समक्ष सब्जी व्यापारी संघ द्वारा एवं पुराने एसबीआई बैंक के सामने शिक्षकों द्वारा भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। फवारा चौक पर भी व्यापारियों द्वारा प्रति वर्ष अनुसार भंडारा प्रसादी के स्टाल लगाए गए। संपूर्ण नगर में तप्ती जन्मोत्सव पर 300 से अधिक भंडारा प्रसादी के स्टाल लगाए जाने का अनुमान है। ढाबा संचालकों के संग ने बस स्टैंड मुलताई पर भंडारा प्रसादी के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया।

समर्पित और निःस्वार्थ चिकित्सकों का लायंस क्लब बैतूल सिटी ने किया सम्मान

बैतूल। डॉक्टर्स डे के अवसर पर लायंस क्लब बैतूल सिटी द्वारा जिला चिकित्सालय बैतूल में सेवा भाव और अद्भुत समर्पण से कार्यरत चिकित्सकों का गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लायंस क्लब बैतूल सिटी द्वारा सर्वप्रथम नवागत सीएमएचओ डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े का स्वागत कर सम्मान किया गया। ततपश्चात सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.जगदीश घोरे, आरएमओ डॉ.रानू वर्मा, सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉ.प्रदीप धाकड़, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ.रूपेश पद्माकर एवं समस्त उपस्थित चिकित्सकों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ.मनोज कुमार हुरमाड़े ने सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स-डे की शुभकामनाएं दी। साथ ही लायंस क्लब द्वारा किये जा रहे विभिन्न जनहित एवं सामाजिक कार्यो की सार्थक व्याख्या की। डॉ हुरमाड़े द्वारा जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहा कि उनका उद्देश्य जिले के अंतिम गांव के अंतिम घर के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। जिले की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, इसके लिए वह कटिबद्ध है। उक्त कार्यो के लिये समस्त चिकित्सकों को अपना सामाजिक एवं शासकीय कार्य दायित्वों को गंभीरता से पालन करने के लिए कहा गया। क्लब के पदाधिकारियों ने कर्तव्यनिष्ठ, सहृदय और परिश्रमी डॉक्टरों को सम्मान-पत्र एवं सुंदर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके मानवता के प्रति निस्वार्थ योगदान के लिए गहन कृतज्ञता व्यक्त की।

अस्पताल परिसर में किया पौधारोपण

कार्यक्रम के दौरान लायंस क्लब बैतूल सिटी द्वारा चिकित्सालय परिसर में वातावरण को और अधिक शुद्ध, हरित और सौंदर्यकारी बनाने के लिए पौधरोपण का भी आयोजन किया गया। इस पौधरोपण का उद्देश्य अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध वायु और शांत वातावरण उपलब्ध कराना था, ताकि उनका इलाज और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रक्रिया अधिक सहज और सकारात्मक हो सके। क्लब अध्यक्ष एमजेएस लायन बीआर कुबड़े ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि चिकित्सक न केवल मरीजों का इलाज करते हैं, बल्कि समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने की आधारशिला भी रखते हैं। पौधरोपण के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं, ताकि भावी पीढ़ियों को भी हरियाली और स्वच्छता का लाभ मिल सके। सम्मान समारोह में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ वंदना धाकड़, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ रोहित पराते, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ विनोद बर्डे, बाल्यरोग विशेषज्ञ डॉ सुरेन्द्र कुशवाहा, मनोरोग चिकित्सक डॉ संजय खातरकर, मेडिसिन पीजीएमओ डॉ तरूण साहू, सर्जन पीजीएमओ डॉ गौरव कंच, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ चित्रकला पाटिल, पीजीएमओ गायनिक डॉ रूपल श्रीवास्तव, पीजीएमओ गायनिक डॉ ईशा डेनियल, पीजीएमओ पैथोलॉजी डॉ अंकिता सिते एवं समस्त डीआरपी प्रशिक्षु चिकित्सक मौजूद रहे।

दो अलग-अलग घरों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा

दोनों आरोपी गिरफ्तार, लाखों का मशरूका बरामद

बैतूल। थाना सारणी अंतर्गत चौकी पाथाखेड़ा पुलिस ने दो अलग-अलग चोरी के मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,60,000 से अधिक मूल्य का मशरूका बरामद किया है। फरियादी रामप्रसाद आहके ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 जून को वह अपने परिवार सहित भोपाल गया था। 24जून को जब वह वापस लौटा, तो पाया कि घर का मुख्य ताला एवं अलमारी का ताला टूटा हुआ है। अलमारी से सोने का हार एवं रियलमी कंपनी का टैबलेट चोरी हो चुका था। मामले की सूचना मिलते ही चौकी पाथाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित विवेचना प्रारंभ की। तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर की सूचना पर अम्मू उर्फ आमिर खान पिता निसार खान निवासी बगडोना और आदिल अफसार पिता आमीन अंसारी निवासी शोभापुर कॉलोनी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से एक सोने का हार, एक रियलमी टैबलेट बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 है। वहीं फरियादी उमेश विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 24 जून को अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इंदौर गया था। 26 जून को घर वापस आने पर उसने पाया कि घर का मुख्य दरवाजे का ताला एवं अलमारी का ताला टूटा हुआ है। अलमारी से 15,000 नकद राशि एवं एक जोड़ी जूते चोरी हो गए थे। दोनों ही आरोपियों को पुनः पूछताछ में इस घटना में भी संलिप्त पाया गया। आरोपियों के कब्जे से 10,000 नकद, एक जोड़ी जूते बरामद किए गए। आरोपियों को न्यायालय बैतूल में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाही में निरीक्षक जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक आशीष कुमरे, सउनि हरिनारायण यादव, प्र.आर. मनोज डेहरिया, प्र.आर. ज्ञानसिंह टेकाम, आरक्षक रविनोहन, आरक्षक राकेश करपे, आरक्षक सुभाष मंडलोई, आरक्षक मोहित भाटी की सराहनीय भूमिका रही।

हत्या की योजना बना रहा कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

देशी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस एवं एक्सयूवी कार जब्त

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने कुख्यात अपराधी रिंकू उर्फ राहुल राठौर को एक देशी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस एवं एक महिंद्रा एक्सयूवी कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हत्या की योजना बनाकर हथियार सहित सोनाघाटी क्षेत्र में घूम रहा था। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर अपराधी, जो वर्तमान में हत्या के मामले में जमानत पर है, अपनी सिल्वर रंग की महिंद्रा एक्सयूवी कार में पिस्टल लेकर सोनाघाटी ब्रिज क्षेत्र में अपने पुराने दुश्मन की हत्या की नीयत से घूम रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित की गई और बताए गए स्थान पर रवाना हुई। सोनाघाटी ओवरब्रिज के नीचे, झाड़ेगांव रोड पर एक सिल्वर एक्सयूवी कार आती हुई दिखी, जिसे पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर साक्षियों की उपस्थिति में रोका। आरोपी ने भागने का प्रयास किया, किंतु पुलिस की तत्परता से उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिंकू उर्फ राहुल पिता रमेश राठौर निवासी विनोबा नगर, गंज बैतूल बताया। उसकी तलाशी लेने पर कमर से एक देशी पिस्टल (मूल्य लगभग 37,500) एवं उसमें लगी मैगजीन में 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही महिंद्रा एक्सयूवी (क्रमांक यूपी 83 एएफ8888) वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत 15,00,000 है, जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली बैतूल में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आरोपी पर दर्ज है 11 गंभीर मामले : आरोपी रिंकू उर्फ राहुल राठौर पर पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, चोरी, नकबजनी, बलात्कार, मारपीट जैसे 11 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह वर्ष 2014 के एक हत्या प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा पाए जाने के बाद वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा है। पिस्टल एवं कारतूस की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की तलाश जारी है। इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, उप निरीक्षक राकेश सरयाम, नरेंद्र उइके, सउनि प्रआर तरुण पटेल, प्रआर शिव कुमार, आर. नितिन, आर. अनिल, तथा आर. प्रदीप, आर. राजेंद्र धारसे साइबर सेल की विशेष भूमिका रही।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

बैतूल। जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त ने जिले के महाविद्यालय, उमावि, हाईस्कूल, छात्रावास संस्था प्रमुखों को उनकी संस्था एवं अधीनस्थ संस्थाओं के विद्यार्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन संस्था स्तर पर एवं नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेन्टर के माध्यम से शतप्रतिशत कराया जाकर शिक्षण संस्था एवं छात्रावास के सूचना पटल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की प्रति चस्पा किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुक्त अनुसूचित जाति विकास एवं आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 वी से महाविद्यालय स्तर तक के क्रियान्वयन के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों के लिए निर्देश जारी किये गए है, जिसमें छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

जब शासन प्रशासन से उम्मीदें टूटीं, तो खुद उठाया फावड़ा

धौल के ग्रामीणों ने बना दी एक किलोमीटर सड़क

बैतूल। जब नेता खामोश हो गए, सिस्टम ने मुंह मोड़ लिया, तब धौल गांव के लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। कीचड़ और जर्जर रास्ते की मार झेल रहे ग्रामीणों ने उम्मीदों की जगह जमीनी हकीकत को चुना और अपनी मेहनत, चंदा व किराए की जेसीबी से एक किलोमीटर सडक़ तैयार कर डाली। ब्लाक बैतूल के ग्राम धौल के ग्रामीण वर्षों से कच्ची सडक़ की परेशानी झेल रहे थे। धौल ढाना से ग्राम लापाझिरी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता ही एकमात्र सहारा था। बारिश में यह रास्ता कीचड़ से भर जाता और आवागमन ठप हो जाता। इस मार्ग से किसानों के खेत भी जुड़े हुए

हैं, जिससे बरसात के मौसम में खेती तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रतिनिधियों, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद से गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी सहयोग नहीं मिला। ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद सभी भाजपा से जुड़े होने के बावजूद इस समस्या की अनदेखी करते रहे। जब ग्रामीणों ने देखा कि कहीं से उम्मीद नहीं बची, तो उन्होंने स्वयं सडक़ बनाने का निर्णय लिया। गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा किया। कुल 50 हजार रुपये जमा किए गए। फिर जेसीबी किराए पर लेकर बोल्डर और मुरम निकलवाए गए। ट्रैक्टर-ट्रालियों की मदद से 5 किलोमीटर लंबे कच्चे मार्ग में से एक किलोमीटर हिस्से पर एक फीट ऊंची सडक़ तैयार कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्य सिर्फ शुरुआत है, बाकी हिस्से की सडक़ भी ग्रामीण अपने प्रयासों से बनाना चाहते हैं। इस कार्य में उपसरपंच आशाराम वरकडे, रतन भलावी, माडुसिंह वरकड़े, सिडुसिंह वरकड़े, अशोक वरकड़े, जयपाल वरकड़े, शिवकिशोर वरकड़े, नंदकिशोर वरकड़े, कुंदन भलावीं, कीर्तिराम वरकड़े, भारत वरकड़े, बलवंत वरकड़े, रामकिशोर धुर्वे, प्रेम भलावीं, मूलचंद वरकड़े, लक्ष्मण धुर्वे, सेवकराम गावंडे, रामपाल वरकड़े, भगु वरकड़े, राजू वरकड़े, संतु काकोडया, रामसिंग वरकड़े, जग्गू भलावीं, फाटू उइके, चेतनराम इंगरे सहित दर्जनों ग्रामीणों ने योगदान दिया। रतन भलावीं ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से इस विषय पर चुप्पी साध ली थी। सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों से मदद की मांग की गई लेकिन नतीजा शून्य रहा। इसलिए गांववासियों ने स्वयं आगे बढक़र कार्य किया और आने वाले समय में बाकी सडक़ भी ग्रामीण अपने सहयोग से बना लेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के वन्य-जीव रेस्क्यू सेंटर विकसित करने के निर्देश पर अमल

वनतारा जैसे नवाचारों को अपनाने से जियो और जीने दो वन्य-जीव संरक्षण ईको-सिस्टम बनेगा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में 'जियो और जीने दो' की भावना को केंद्र में रखकर सह-अस्तित्व आधारित ईको-सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और वनवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कई नवाचार किए जा रहे हैं इनमें वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण और प्रबंधन में उच्च तकनीक का अनुप्रयोग, गुजरात के 'वनतारा' से प्रेरित रैस्क्यू सेंटर, दुर्लभ जीवों जैसे चीते, घड़ियाल एवं कछुओं के एक अभयारण्य से दूसरे में पुनर्स्थापन और संरक्षित क्षेत्रों की फेंसिंग शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग के अधिकारियों को गुजरात के 'वनतारा' वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का अध्ययन कर प्रदेश में भी ऐसा ही रेस्क्यू और एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल वन्यजीवों के संरक्षण और पुनर्वास में एक नई मिसाल पेश करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के घने वनों और वन्यजीव पर्यटन को राजस्व वृद्धि का एक प्रमुख माध्यम बताया। उन्होंने वन अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाओं और उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश में वन क्षेत्र और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। जैव-विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई स्थलों को जैव-विविधता विरासत घोषित किया गया है। वन-अग्नि की घटनाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया अब पहले से अधिक त्वरित हुई है, जो प्रभावी वन प्रबंधन को दर्शाता है।

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उठाए गए प्रमुख कदम

मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे प्रदेश की छवि टाइगर स्टेट के रूप में और मजबूत हो रही है। प्रदेश में अब 9 टाइगर रिजर्व हो गये हैं। बाघ संरक्षण के साथ-साथ ये रिजर्व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं। टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए 'बफर-सफर' योजना के अंतर्गत अनेक नई गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। अब पर्यटक प्राकृतिक स्थलों, वन और वन्य-प्राणी दर्शन के साथ ईको-पर्यटन गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और कोर क्षेत्रों पर दबाव भी कम होगा।

प्रदेश में 15,000 से अधिक वन समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, जिनकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाया जा रहा है। प्रदेश में आधुनिक चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर्स विकसित किये जा रहे हैं। उज्जैन और जबलपुर में उन्नत सुविधाओं से युक्त नये चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर शीघ्र ही स्थापित किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर, तासी और बालाघाट के सोनेवानी क्षेत्र में नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जा रहे हैं, जो वन्यजीव आवासों की रक्षा करेंगे।

अफ्रीका से लाए गए चीतों की कूनो में सफल पुनर्स्थापना के बाद इन चीतों को प्रदेश एंव देश के दूसरे अभयारण्यों में बसाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश के बुंदेलखंड वन क्षेत्रों में फैले हुए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीता पुनर्स्थापना की तैयारियाँ चल रही हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होगी। जलीय जीव संरक्षण के रूप में नर्मदा में महाशीर मछली जैसे जलजीवों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। चंबल में कछुए, मगरमच्छ एवं घड़ियाल एवं गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए केंद्र पहले से ही स्थापित हैं। इनमें जलीय जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन्हें प्रदेश के साथ ही देश भर में भेजा जा रहा है। मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग की जा रही है। इससे वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

हाथियों की सुरक्षा हेतु विशेष योजना

प्रदेश सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा और अनुश्रवण के लिए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल ?1 करोड़ 52 लाख 54 हजार खर्च किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ?20 करोड़ और 2026-27 के लिए ?25 करोड़ 59 लाख 15 हजार का प्रावधान किया गया है। इस तरह वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक योजना का कुल आकार ?47 करोड़ 11 लाख 69 हजार रहेगा। हाथियों के आवागमन की मॉनिटरिंग के कॉलर आईडी लगाये जा रहे हैं। इन योजनाओं से हाथियों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

वनवासियों के अधिकारों का सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व की घोषणा से जनजातीय समुदायों और वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा और उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। सह-अस्तित्व के लिए सह-प्रबंधन की नीति अपनाई जाएगी और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के विजन के अनुरूप उनके निर्देशन में मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिये एक अग्रणी मॉडल के रूप में उभर रहा है। यहां जैव विविधता, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और जनजातीय आजीविका का संतुलित एवं वन्य-जीवों के साथ सह-अस्तित्व का इको सिस्टम विकसित हो रहा है।

संक्षिप्त समाचार

अमरसिंह को मिली खेत तालाब की सौगात

हरदा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से सरकार और समाज के द्वारा पुरानी जल संरचनाओं में जल भरण, जल के प्रबंधन तथा नई जल संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जल के बिना जीवन की परिकल्पना शून्य है और इसके बिना न तो कृषि संभव है, न ही उद्योग, और न ही हमारी दैनिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। जल का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। जिले की जनपद पंचायत हरदा के ग्राम झालवा निवासी किसान अमरसिंह निर्भयसिंह को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नवीन खेत तालाब उपहार में मिला। खेत तालाब बनने से अब अमरसिंह को फसल की सिंचाई के लिए वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खेत तालाब का निर्माण होने से अमरसिंह बहुत खुश है। अमरसिंह की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नही थी कि वह फसलों की सिंचाई या अन्य कार्य के लिए सिंचाई का साधन जुटा सके। अमरसिंह बताता है कि खेती का कार्य पूरी तरह वर्षा जल पर निर्भर था, जिस वर्ष अच्छी बारिश नहीं होती थी, उस वर्ष सिंचाई का साधन न होने के कारण फसलें सूख जाती थी। खेत तालाब का निर्माण हो जाने से अब उसे इस चिंता से मुक्ति मिल गई है। इसके लिए वह प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त करता है।

खिवनी अभ्यारण्य की अधिसूचना संबंधी कार्यवाही वर्तमान में लंबित

सीहोर (निप्र)। खिवनी अभ्यारण्य के संबंध में वन मंडल अधिकारी श्री मगन सिंह डावर ने बताया कि सीहोर वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र इछावर एवं लाड़कुई के आरक्षित वनों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26ए के अंतर्गत अभ्यारण्य के रूप मे खिवनी अभ्यारण्य के रूप मे अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वन मंडल अधिकारी श्री डावर ने बताया कि खिवनी अभ्यारण्य की अधिसूचना संबंधी कार्यवाही वर्तमान में लंबित है।

सीहोर व्यापार मेले में स्टॉल लगाकर की गई सहकारी संस्थाओं के उत्पादों की बिक्री

सीहोर (निप्र)। भारत सरकार के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग एवं नगर पालिका परिषद द्वारा सीहोर स्थित बाल विहार ग्राउंड में चल रहे सीहोर व्यापार मेले में जिले की अनेक प्रसिद्ध वस्तुओं, औषधियों, खाद्य सामग्रियों आदि की बिक्री और शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए 26 जून से 29 जून तक स्टॉल लगाए गए। इसके तहत रागिनी काष्ठ कला सहकारी समिति मर्यादित बुधनी द्वारा तैयार किए गए लकड़ी के खिलौने, प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित रेहटी द्वारा तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधियां, प्राथमिक महिला आजीविका बहु प्रयोजन सहकारी संस्था द्वारा तैयार किए गए लकड़ी के खिलौने, नमकीन- मिक्चर, जूट के बैग, पर्स, कॉटन के कपड़े एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीहोर द्वारा किसानों एवं आम जनमानस के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए और संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की गई। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्राम स्तर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता का प्रचार प्रसार एवं सहकारी योजनाओं के प्रति जनता करने, सहकारिता की कल्याणकारी योजनाओं तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों की जानकारी प्रदेश के सुदूर अंचलों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सलाहकार परिवार नियोजन कार्यक्रम डॉ.पूनम मिश्रा ने की परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा

बैतूल (निप्र)। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमपुर में 30 जून 2025 को राज्य सलाहकार परिवार नियोजन कार्यक्रम एनएमएच भोपाल डॉ.पूनम मिश्रा द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। डॉ.मिश्रा द्वारा परिवार कल्याण के साधनों की उपलब्धता, खर्च एवं मांग ऑनलाइन एंडेन के माध्यम से करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने संस्थागत प्रसव के 30 प्रतिशत पीपीआईयूसीडी लगाने, अंतरा इंजेक्शन एवं छाया, गर्भनिरोधक साधनों की उपयोगिता बढ़ाने के भी निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ.दीपक निगवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ विनोद शाक्य, डीसीएम श्री कमलेश मसीह, बीईई श्रीमती चन्द्रगीता पदमाकर एवं एएनएम, आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम ने घाट व पुल पुलियाओं का किया निरीक्षण

हरदा (निप्र)। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने सभी पुल पुलियाओं व घाटों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिये है। साथ ही होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिये है। डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमाण्डेंट श्री मयंक जैन ने बताया कि होमगार्ड व एसडीआरएफ के रस्क्यू दल ने सोमवार को खेड़ीपुरा नाका, अजनल नदी, गुप्तेशर मंदिर, छोटा पुल, दोगने जी की पुलिया तथा रन्हाई पुलिया का निरीक्षण किया। उन्होने बताया कि जिले में लगातार बारिश को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा

भारत-जर्मनी सहयोग से सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण पर नीति आयोग की 3 जुलाई को राज्य स्तरीय वर्कशॉप

भोपाल (नप्र)। सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी क्रम में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में निजी उद्योग की भूमिका और सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत जर्मन सहयोग परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कार्यशाला भोपाल के कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल में 3 जुलाई को सुबह दस बजे से आयोजित की गई है।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश के विभिन्न विभाग, जिलों के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, जर्मनी की संस्था जीआईजेड के प्रतिनिधियों से सतत विकास के लक्ष्यों और उनके स्थानीयकरण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण में तेजी आई है और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा मिला।

प्रदेश में उत्पादन और जिम्मेदार पूर्ण उपभोग, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ स्वच्छता, शहरीकरण, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय काम हुआ है। मध्यप्रदेश के प्रयासों से 2.30 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करते हुए मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने के लिए आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत के प्रावधान के लिए जल जीवन मिशन में उल्लेखनीय काम हुआ है। मध्यप्रदेश देश के उन पहले राज्यों में से एक है जिसने भोपाल शहर के लिए स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा की और इंदौर नगर निगम में ग्रीन म्युनिसिपल बांड के माध्यम से वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाई। कार्यशाला में जर्मन दूतावास और यूएनडीपी के प्रतिनिधि, भारत जर्मन सहयोग परियोजना की प्रमुख श्रीमती हेनरी पेईचर्ट, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री राजीव कुमार सेन और सतत विकास लक्षण के क्रियान्वयन से जुड़े विषय विशेषज्ञ, आर्थिक सलाहकार, कॉर्पोरेट भागीदारी से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान ने प्रत्येक नागरिक को दिया है जल संरक्षण का संदेश : विधायक श्री राय

सीहोर (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर सीहोर जनपद पंचायत परिसर में जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम विधायक श्री सुदेश राय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नावड़ी बाई एवं कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी जनपद पंचायतों के शासकीय सेवकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।

इस अवसर पर विधायक श्री सुदेश राय ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में चलाया गया यह अभियान भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल संकट से बचाव के लिए एक प्रभावी कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान ने प्रदेश के साथ ही जिले के प्रत्येक नागरिक को जल एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया है। जल प्रकृति द्वारा दी गई एक अमूल्य संपदा है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नही है। हम सभी का यह दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें। कार्यक्रम

में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान का भले ही आज समापन हो रहा है पर हम सभी को जल का निरंतर संरक्षण करते हुए आमजन को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है।

उन्होंने सभी पंचायत सचिवों, सरंपचों, शासकीय सेवकों और नागरिकों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आगे भी ऐसे ही जल संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करते रहें और जल संरक्षण को आमजन की आदत बनाने करने का प्रयास करें। ताकि प्रकृति के इस अमृत रूपी जल को सहेजा जा सके। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं शासकीय सेवक उपस्थित थे।

इन्हें किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आष्टा जनपद के जीआरएस श्री मनोहर मेवाडा, पंचायत सचिव श्री लखन सिहं ठाकुर, उपयंत्री श्री उमेश शर्मा और श्री कुलदीप उपाध्याय का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार इछावर जनपद के जीआरएस श्री राकेश कुमार बकोरिया, पंचायत सचिव श्री श्री हरिकिशन मेवाडा, उपयंत्री श्रीमति प्रियंका बघेल को सम्मानित किया गया। बुधनी जनपद के जीआरएस श्री हरिश यादव, पंचायत सचिव श्रीसत्रामउ अभिनाश चौहान और उपयंत्री श्री अतुल मिश्रा को सम्मानित किया गया। भैरूंदा जनपद के जीआरएस श्री राजेश हरियाले, पंचायत सचिव श्री विष्णु हरिव्यासी और उपयंत्री श्री राकेश कुशवाह को सम्मानित किया गया। सीहोर जनपद के जीआरएस श्री रामकृष्ण मीना, पंचायत सचिव श्री शिवराज सिंह और उपयंत्री श्री केके श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हुआ

मुख्यमंत्री जी का लाइव उद्बोधन जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में देखा सुना गया

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ, मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विदिशा जिले में भी 30 मार्च से 30 जून तक अभियान का क्रियान्वयन किया गया था। अभियान के समापन अवसर पर जिला पंचायत के सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

जिला स्तर पर खंडवा में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया था। जिला पंचायत के सभा कक्ष में एलईडी और साउंड सिस्टम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लाइव उद्बोधन देखा और सुना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी , शमशाबाद विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा के अलावा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी गण तथा उपयंत्री, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विदिशा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग और

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किए गए कार्यों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित : जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिला पंचायत में आयोजित समापन समारोह कार्यक्रम में जिला पंचायत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया है, जिनमें ग्राम पंचायत खामखेड़ा कस्बा एवं पीपलखेड़ा कलां के उप यंत्री श्री दुष्यंत सिंह चंदेल, सतपाड़ाहाट के उप यंत्री श्री आशीष जैन, पठारी के उपयंत्री श्री देवेंद्र ठाकुर, हैदरगढ़ के उपयंत्री श्री दिनेश दांगी, ग्राम पंचायत उकायला की सरपंच श्रीमती सरिता विमल सोलंकी, ग्राम पंचायत मुरवास के सरपंच श्री उमर खान, ग्राम पंचायत भूत परासी के सरपंच श्री मजहर खान, ग्राम पंचायत बरमढ़ी के सचिव श्री लक्ष्मण सिंह रघुवंशी, ग्राम पंचायत स्यारी के ग्राम रोजगार सहायक श्री शैलेंद्र रघुवंशी, पठारी के ग्राम रोजगार सहायक श्री मुकेश जैन, लखार एवं आमखेड़ा कालू के ग्राम रोजगार सहायक श्री टम्पू, नारायणपुर कला के ग्राम रोजगार सहायक श्री रामबाबू भील, काला देव के ग्राम रोजगार सहायक श्री याकूब अली और सलैया के ग्राम रोजगार सहायक श्री दीपेश चैकसे शामिल हैं।

नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृति योजना पर 3 जुलाई को एक दिवसीय कार्यशाला

भोपाल (नप्र) ।प्रदेश में राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गुरुवार 3 जुलाई को राजधानी भोपाल के होटल अशोका लेक व्यू में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में केन्द्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार श्री राघवेन्द्र खरे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत शासकीय, अनुदान प्राप्त या नगरीय निकाय के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रुपये 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिये आयोजित होने वाली चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।उक्त छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष छात्रवृति की राशि प्राप्त होती है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीयन किया जाता है। पंजीयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के चलते विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रह जाए इसी उद्देश्य के दृष्टिगत और योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारी, कर्मचारी तथा समस्त जिले से एनएमएमएसएस के नोडल अधिकारी तथा उनके सहायक सहभागिता करेंगे।

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन और विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों तथा निराकरण की समीक्षा की और सीएमएचओ, सिविल सर्जन, ई पीएचई तथा जिला शिक्षा अधिकारी सहित कम प्रगति वाले अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन का गंभीरतापूर्वक समयावधि में निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को भी सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गैरतगंज, गौहरगंज तथा बेगमगंज एसडीएम को शिकायतों के निराकरण हेतु और अधिक मेहनत करने के लिए कहा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति कार्य विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का शीघ्र निराकरण होने पर अधिकारियों की सराहना की। महिला बाल विकास विभाग की 100 दिवस से अधिक समयावधि की 2653 शिकायतों में से लगभग 1100 शिकायतों का निराकरण होने पर सराहना करते हुए शेष शिकायतों का भी निराकरण कराने के लिए कहा।

बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का निम्न गुणवत्ता से निराकरण किए जाने पर नाराजगी व्यक्त कर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य विभाग, कृषि विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की शिकायतें नॉन अटेन्डेन्ट रहने पर भी नाराजगी व्यक्त कर संबंधितों को गंभीरतापूर्वक निराकरण सुनिश्चित कराने के लिए कहा। बैठक में मप्र विद्युत वितरण कम्पनी के डीईई श्री पराग धावड़े को समाधान ऑनलाईन में प्रदेश स्तर पर जिले की रैंकिंग 21 नम्बर होने पर संतोषजनक जबाव नहीं देने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास निर्माण की समीक्षा के दौरान अपूर्ण आवासों की संख्या अधिक होने पर पीओ डूडा को आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही जियो टैगिंग कार्य भी शत-प्रतिशत कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में खरीफ 2025 में उर्वरक की उपलब्ध एवं वितरण की जानकारी लेते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि किसानों को मांग अनुरूप खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। साथ ही सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में उर्वरक की उपलब्धता का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मूंग तथा उड़द के समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु किसान पंजीयन की जानकारी और उपार्जन तैयारियों की जानकारी ली। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों को उद्यानिकी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने तथा विभागीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

अब किसान मोहनलाल मूंग व अन्य फसलों का लाभ ले सकेगा

हरदा (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान ने प्रदेश के किसानों के जीवन में आशाजनक बदलाव लाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हरदा जिले की ग्राम पंचायत करनपुरा निवासी श्री मोहनलाल राधाकिशन ने कूप के पास डगवेल का निर्माण कराया है, जिससे उनके कुएं में वर्षा के पानी को डगवेल में एकत्रित कर कुएं में डाला जा रहा है। इस कार्य से उनके कुएं में जल स्तर में सुधार आया है। हितग्राही मोहनलाल को मनरेगा योजना के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान जल के महत्व को समझाया गया तथा भू-जल को बढाने के लिये प्रेरित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की।

सीबीआई की एमपी-सीजी सहित 6 राज्यों में छापेमारी

3 डॉक्टर्स समेत 6 गिरफ्तार, 55 लाख रिश्वत लेकर अनुकूल रिपोर्ट देने का मामला

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मान्यता के लिए मेडिकल कॉलेज के पक्ष में 55 लाख रुपए घूस लेकर अनुकूल रिपोर्ट देने के मामले में तीन डॉक्टरों समेत छह लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में 40 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, जिसमें नए खुलासे होने की उम्मीद है। सीबीआई के मुताबिक, यह छापा छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से जुड़ा है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल से मान्यता दिलाने के बदले 55 लाख रुपए रिश्वत दी। वैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। संस्थान के पदाधिकारी और बिचौलिए, निरीक्षण के लिए नियुक्त डॉक्टरों से संपर्क कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।

जाल बिछाकर रंगे हाथों किया गिरफ्तार: सीबीआई ने पुख्ता सूचना मिलने पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। रिश्वत के लेन-देन के दौरान सभी 6 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में 3 डॉक्टर, संस्थान के पदाधिकारी और 3 बिचौलिए शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित न्यायालयों में पेश किया गया है।

देशभर में छापेमारी और दस्तावेजी जांच: सीबीआई ने सोमवार को कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे थे।

प्रदेश के 18 आयुर्वेद कॉलेजों को मिली मान्यता

- मप्र में बीएएमएस की 3 हजार सीटें, 16 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता पर निर्णय होना बाकी

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) नई दिल्ली ने सत्र 2025-26 के लिए मध्यप्रदेश के 18 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी है। इनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर के 7 शासकीय आयुर्वेद कॉलेज और 11 निजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। एनसीआईएसएम ने देश में दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा आयुर्वेद कॉलेजों को मान्यता दी है। हालांकि, प्रदेश के 16 अन्य कॉलेजों सहित देशभर के 482 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता पर निर्णय होना बाकी है।

मान्यता प्राप्त कॉलेजों और सीटों का विवरण: भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज को 75 यूजी (बीएएमएस) और 74 पीजी सीटें मिली हैं। वहीं, भोपाल के स्कूल ऑफ आयुर्वेद साइंस, सरदार अजीत सिंह स्मृति आयुर्वेद कॉलेज, रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेद और मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को 100-100 यूजी (बीएएमएस) सीटों पर मान्यता दी गई है।

प्रवेश प्रक्रिया और सीटों की संख्या: आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश सहित देशभर के सभी आयुर्वेद कॉलेजों में प्रवेश नीट 2025-26 के परिणामों के आधार पर ही होंगे। मध्यप्रदेश में यूजी की लगभग 3000 सीटों सहित देशभर के 598 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में 42 हजार से अधिक सीटें हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जबलपुर बनेगा पर्यटन का नया केन्द्र : मंत्री सिंह

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर जबलपुर अब पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान की ओर अग्रसर है। पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के उद्देश्य से मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित ठाकुरताल क्षेत्र को एक एमिनेंट पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना में 'फॉरेस्ट सफारी - जू कम रेस्क्यू सेंटर' और संग्राम-सागर तालाब के समग्र विकास को भी सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने वन मंडल अधिकारी श्री ऋषि मिश्रा एवं कंसलटेंट श्री दुबे के साथ विस्तृत चर्चा कर योजना की रूपरेखा तैयार की।लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया परियोजना को और अधिक गरिमा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर विकसित करने की घोषणा की है। यह निर्णय जबलपुर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को और भी सशक्त करेगा। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने इस उपलब्धि के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है।मंत्री श्री सिंह ने बताया यह पर्यटन परियोजना लगभग 85 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी जिसमें पर्यटकों को प्राकृतिक वन्य जीवन और आधुनिक तकनीकों का समन्वित अनुभव मिलेगा। इस केंद्र में रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई पार्क, तथा लॉन्ग कार्निवल जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी, जिसमें येलो टाइगर, व्हाइट टाइगर, पैंथर, लायन और भालू जैसे आकर्षक वन्य-जीव रहेंगे। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल हाउस में मगरमच्छ और सांप और एग्जॉटिक और नेटिव बर्ड्स के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे। ज़ेब्रा और जिराफ के लिए एक अलग एग्जॉटिक पार्क, वाटर इंटरप्रिटेशन सेंटर, और स्पीशीज वाइज इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे अनेक नवाचार इस परियोजना की विशेषता होगी।

मुख्यमंत्री का इंटरएक्टिव सेशन और उद्योगपतियों से संवाद 7 को

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में चल रही औद्योगिक संवाद श्रृंखला में प्रमुख इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में 7 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। बैंगलुरु और सूरत में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब लुधियाना में तीसरा इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपोर्चूनिटीज इन मध्यप्रदेश आयोजित होगा।ॉमुख्यमंत्री डॉ. यादव लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे। यह आयोजन केवल विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें संभावित निवेश प्रस्तावों पर ठोस चर्चा भी की जाएगी। मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति, सेक्टर-फोकस्ड रणनीतियां और ग्राउंड-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इस संवाद का केंद्रीय आकर्षण होंगे। लुधियाना की पहचान भारत के विनिर्माण हब के रूप में रही है, विशेष रूप से वस्त्र और मशीनरी निर्माण में लुधियाना की विशेष पहचान है।

दाएं-बाएं करने वालों को होगी दिक्कत- खंडेलवाल

खंडेलवाल बोले- जो कार्यकर्ता समर्पित है, उसे सम्मान मिलेगा, प्रधान ने सौंपा पार्टी का झंडा

भोपाल (नप्र)। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्यप्रदेश भाजपा का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित निर्वाचन समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र दिया और फूल माला पहनाकर स्वागत किया।

खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा- हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप आचरण रखें। जो कार्यकर्ता समर्पित है, उसका सम्मान होगा। जो दाएं-बाएं करेगा उसे दिक्कत आएगी।

खंडेलवाल बोले- हमारी पार्टी में अनुशासन है। इतने बड़े-बड़े चुनाव हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग एक ही नामांकन भरते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं। जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है, आप वार्ड का भी करवा दो तो

हम सम्मान कर देंगे। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे।

एमपी में देर रात 4 आईएएस के तबादले

अनिल सुचारी सागर संभागायुक्त, संजीव झा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने सुखवीर प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी होंगे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मंगलवार देर रात राज्य शासन ने 4 आईएएस अफसरों की पोस्टिंग बदली है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सीनियर आईएएस अनिल सुचारी को सागर संभागायुक्त बनाया गया है। ये पद तीस जून को खाली हुआ था। सुचारी अब तक सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव थे। राजस्व मंडल सदस्य संजीव कुमार झा अब नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। इसी के साथ निवर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी बनाए गए हैं। इससे पहले भी वे इस विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से इन दोनों ही अफसरों को पदस्थ करने को लेकर फैसला पिछले माह ही हो गया था, लेकिन सरकार ने इसके आदेश अब जारी किए हैं। सुखवीर सिंह के जॉइन करने के बाद ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

रघुराज एमआर को सचिव श्रम विभाग की जिम्मेदारी

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व रोजगार विभाग रघुराज एमआर को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है। मप्र मानव अधिकार आयोग के प्रमुख सचिव मुकेश चंद्र गुप्ता को राजस्व मंडल सदस्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रमुख सचिव खनिज साधन उमाकांत उमराव, रघुराज एमआर के जॉइन करने के बाद प्रमुख सचिव श्रम विभाग के दायित्व से मुक्त होंगे। उनके पास पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा।

खंडवा अस्पताल में डॉक्टर को मुक्के और कुर्सी मारी

महिला की हार्ट अटैक से मौत से बेटा गुस्सा गया, ईसीजी मशीन फेंककर मारी

खंडवा (नप्र)। खंडवा जिला अस्पताल में बुधवार सुबह इलाज के दौरान एक महिला पेशेंट की मौत हो गई। इसके बाद महिला के बेटे ने इलाज कर रहे डॉक्टर को मुक्कों से पीटा, कुर्सी और ईसीजी मशीन फेंककर मारी। घटना के बाद डॉक्टरों ने पुलिस थाने तक रैली निकाली और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों ने बताया कि महिला गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला को आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया था: मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. रणजीत बडौले ने बताया कि 2 जुलाई की रात एक बजे 42 वर्षीय रेखा पति धीरज को हृदय संबंधी समस्या कारण इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। प्राथमिक जांच और ईसीजी में हार्ट अटैक की पुष्टि होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। परिजन को मरीज की गंभीर हालत से अवगत कराया गया और हाई रिस्क कंसर्न लिया गया। सुबह 4 बजे दूसरी ईसीजी कराई गई। इसकी रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं दिखा। डॉक्टरों द्वारा सीपीआर

सहित सभी संभव प्रयास किए गए, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। महिला की मौत की सूचना मिलने पर परिजन भड़क गए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जूनियर और सीनियर महिला डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपियों ने जूनियर रेजिडेंट कुलदीप जोशी से मारपीट की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। नर्सिंग स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।

नर्मदापुरम में रिटायरमेंट के दिन डिप्टी रेंजर बर्खास्त

5 साल पुराने 18 लाख के गबन केस में सीसीएफ ने विदाई समारोह के बाद की कार्रवाई

नर्मदापुरम (नप्र)। नर्मदापुरम वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर हरगोविंद मिश्रा को रिटायरमेंट के दिन ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय जांच में 18 लाख रुपए के गबन का आरोप साबित होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) अशोक कुमार चौहान ने यह कार्रवाई की।

सोमवार को जहां सुबह कार्यालय में मिश्रा को विदाई दी गई, वहीं दोपहर में उन्हें बर्खास्तगी का आदेश थमा दिया गया। मामला बानापुरा में पदस्थी के दौरान इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें 150 लोगों के भ्रमण कार्यक्रम में फर्जी बिल लगाकर 18 लाख रुपए का गबन किया गया था।

सुबह कार्यालय में विदाई, दोपहर में हुए बर्खास्त

वन विभाग के डिप्टी रेंजर हरगोविंद मिश्रा को सोमवार को सेवानिवृत्त होना था। सुबह कार्यालय में उन्हें स्टाफ ने विदाई दी। इसके बाद दोपहर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक आशोक कुमार चौहान ने उन्हें सेवा से हटाने का आदेश जारी कर दिया। डिप्टी रेंजर मिश्रा पर बानापुरा में पदस्थ के दौरान इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में समितियों के 150 लोगों को भ्रमण पर ले जाना था। इस भ्रमण कार्यक्रम में लगभग 18 लाख रुपए की अनियमितता की शिकायत की गई थी। तब तत्कालीन डीएफओ अजय पांडे थे।

दूर प्रभारी थे हरगोविंद मिश्रा

शिकायतकर्ता और वन कर्मचारी संघ के संरक्षक मधुकर चतुर्वेदी ने बताया कि 23 जुलाई 2019 को भारत सरकार की ईएसआईपी योजना के तहत 150 ग्रामीणों को महाराष्ट्र रालेगढ़ सिद्धि भ्रमण कराने ले जाया गया था। तब डिप्टी रेंजर तत्कालीन बानापूरा प्रभारी हरगोविंद मिश्रा दूर के प्रभारी थे।

नर्मदापुरम के तत्कालीन डीएफओ अजय पांडे ने 21 जुलाई 2019 को अहमदनगर महाराष्ट्र के डीएफओ को पत्र लिखकर टूर प्रोग्राम भेजा था। 23 जुलाई को भ्रमण दल रवाना हुआ। जो 23 जुलाई से 28जुलाई तक रहा। भ्रमण के दौरान पद्मावती संत निवास रालेगण सिद्धि में 24 जुलाई को रखना और 23, 25 जुलाई को सिंहगड़ होटल शिर्डी में रात्रि रुकना बताया। खोजबीन करने पर जानकारी मिली कि रालेगढ़ सिद्धि में पद्मावती संत निवास नाम की होटल नहीं है। शिर्डी में सिंहगड़ होटल में केवल चाय पानी, नाश्ते की व्यवस्था है। उसमें रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। कैटरिंग के बिल भी गलत बनाए गए।

सभी का काम भुगतान चार फॉरेस्ट गार्ड के खाते में कराए गए। इस पूरे भ्रमण के संबंध में डीएफओ ने स्टेट से अनुमति नहीं ली थी। जबकि नियम अनुसार प्रदेश से बाहर जाने वाले टूर के लिए स्टेट के अधिकारियों की परमिशन जरूरी होती है।

फर्जी बिल लगाकर 18 लाख का गबन

भ्रमण यात्रा में फर्जी बिल लगाकर 18 लाख रुपए का गबन किया गया था। मामला उजागर होने पर सेवानिवृत फॉरेस्ट अधिकारी और वन कर्मचारी संघ के संरक्षक मधुकर चतुर्वेदी ने शिकायत की थी।

मामले में विभाग ने जांच की, इस दौरान डिप्टी रेंजर मिश्रा को अपने बचाव में जवाब देने के लिए कहा गया था। उन्होंने 24 जून को अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद विभाग ने 30 जून को उन्हें सेवा से अलग कर दिया।

होटल में युवती के साथ मिले साहिल को पीटा

उज्जैन में लड़की बोली- डरा-धमकाकर ले गया, केस दर्ज कराया, बजरंग दल वालों ने तोड़फोड़ की

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के घिनोदा गांव के एक होटल में युवती के साथ मिले साहिल नाम के युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले साहिल की लात-घूंसों और बेल्ट से पिटाई की, फिर होटल में तोड़फोड़ कर दी। कुर्सियां और अन्य सामान फेंककर उत्पात मचाया, जिससे डरकर होटल कर्मचारी भाग गए। पुलिस के मुताबिक, पल्या रोड निवासी साहिल शेख मंगलवार को एक युवती को घिनोदा के गायत्री होटल लेकर पहुंचा था। इसकी जानकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मिल गई, जिसके बाद 6-7 कार्यकर्ता होटल पहुंच गए।

कमरे खुलवाकर देखे, अंदर युवक-युवती मिले: होटल मोकड़ी गांव

के राजेंद्र गुर्जर का है, जिसे झिरनिया निवासी यूसुफ चला रहा था। होटल पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कई कमरे खुलवाकर देखे। एक कमरे में युवक-युवती के मिलने पर कार्यकर्ता खिड़की से कमरे में घुस गए और युवक साहिल की जमकर पिटाई की। इस दौरान साहिल हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। वह कहता रहा कि आगे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कार्यकर्ता उसे बेल्ट से पीटते हुए नीचे ले आए।

पुलिस बोली- यूसुफ, साहिल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे: पुलिस के आने से पहले ही वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे और थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होटल संचालक यूसुफ और युवक साहिल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।

युवती के बयान पर साहिल के खिलाफ केस दर्ज: थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पल्या रोड नागदा निवासी साहिल शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(जे), 64(2)(एम), 351(2), 49 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी साहिल शेख से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ समय बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई। बाद में साहिल ने ने जान देने की धमकी देकर दोबारा संपर्क किया और होटल में गलत काम करने के लिए ले गया।